मई 2016

मध्यप्रदेश पंचायिका

पंचायतों की मासिक पत्रिका

|ÉEò¤ÉvÉ ºÉ¨{ÉÉnEò
ºÉ¡ÉÉ¹É Ê¨É¸É

ºÉ¨ÉxÉ´ÉªÉ
¨ÉMÉ±ÉÉ |ÉºÉÉn Ê¨É¸ÉÉ

{É®úÉ¨É¶ÉÇ
Ê¶É´ÉÉxÉÒ ´É¨ÉÉÇ
bÉ. Ê´ÉxÉÉn ªÉÉn´É

ºÉ¨{ÉÉnEò
®úVÉxÉÉ ÊSÉ¡É±É

ºÉ½ªÉÉMÉ
+ÊxÉ±É MÉ{¡ÉÉ

´ÉÉ¤ÉºÉÉ<]
+É¡¨ÉÉ®úÉ¨É ¶É¨ÉÉÇ

+ÉEò±{ÉxÉ
+±{ÉxÉÉ ®úÉ`Éè®
+É±ÉÉEòxÉ MÉ{¡ÉÉ
Ê´ÉxÉªÉ ¶ÉÉEò®ú ®úÉªÉEòú

BEò |ÉÊiÉ : ¤ÉÒºÉ ¯û{ÉªÉ
´ÉÉÌ¹ÉEò : nÉ ºÉÉ ¯û{ÉªÉ

ºÉ¨{ÉEÇò
¨ÉvªÉ|Énä¶É {ÉSÉÉÊªÉEòÉ
¨ÉvªÉ|Énä¶É ¨ÉÉvªÉ¨É
40, |É¶ÉÉºÉÊxÉEò IÉjÉ, +®úä®úÉ Ê½±É
¦ÉÉ{ÉÉ±É-462011
¡òÉxÉ : 2764742, 2551330
¡òèCºÉ : 0755-4228409
Email : panchayika@gmail.com

Eò{ÉªÉÉ ´ÉÉÌ¹ÉEò OÉÉ½Eò ¤ÉxÉxÉ Eò Ê±ÉB +{ÉxÉÉ bÉ}]/
¨ÉxÉÉÒ+Éb®ú ¨ÉvªÉ|Énä¶É ¨ÉÉvªÉ¨É, ¦ÉÉ{ÉÉ±É Eò xÉÉ¨É ºÉ ¦ÉVÉå*

¨ÉvªÉ|Énä¶É {ÉSÉÉÊªÉEòÉ ¨É ´ªÉHò Ê´ÉSÉÉ®ú ±ÉäJÉEòÉ Eò +{ÉxÉ ½þ,
<ºÉEò Ê±ÉB ºÉ¨{ÉÉnEò ÉÒò ºÉ½¨ÉÊiÉ +ÊxÉ´ÉÉªÉÇ xÉ½Ó ½*

<ºÉ +Eò ¨Éå

- **ग्रामोदय :** विकास के संसाधनों को गांव की ओर मोड़ना होगा — 3
- **सम्मान :** ग्रामीण विकास में श्रेष्ठ कार्यों के लिये मध्यप्रदेश को प्रथम पुरस्कार — 5
- **विचार महाकुंभ :** सिंहस्थ सार्वभौम अमृत संदेश विश्व को समर्पित — 8
- **विशेष लेख :** गांधीजी की ग्राम स्वराज अवधारणा पर आधारित ग्रामोदय — 15
- **ग्रामोदय :** सीख समझाईश और समस्या निदान — 21
- **ग्रामोदय-ग्राम संसद :** गाँव की योजना अब गाँव में बनेगी — 22
- **ग्रामोदय : महिला सशक्तीकरण :** राष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल हुईं.... — 25
- **ग्रामोदय : ग्राम विकास :** ग्रामीणों ने खुद तय किया अपना विकास — 27
- **मुख्यमंत्री कन्यादान योजना :** सामाजिक समरसता की मिसाल बना गढ़ाकोटा — 29
- **खास खबरें :** ग्रामोदय से भारत उदय अभियान अब हर वर्ष आयोजित होगा — 30
- **अच्छी पहल :** तालाब से बदली तस्वीर — 32
- **सिंहस्थ विशेष :** अपना सारा काम छोड़ मुख्यमंत्री उज्जैन पहुंचे — 34
- **पंचायत गजट :** जिला पंचायत अध्यक्ष को मिलेगी निज सहायक की सुविधा — 45

आयुक्त की कलम से...

प्रिय पाठको,

गाँवों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने और सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को जन-जन तक पहुँचाने के लिए चलाए जा रहे ग्रामोदय से भारत उदय अभियान की शुरुआत मध्यप्रदेश से हुई। 14 अप्रैल को बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर की जन्मस्थली महू (अम्बेडकर नगर) में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अभियान का शुभारंभ करते हुए गांवों को सशक्त बनाने और महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के सपने को साकार करने की दिशा में कदम बढ़ाने का संकल्प लिया। इस खबर को हमने 'ग्रामोदय' स्तंभ में प्रकाशित किया है। अनुसूचित क्षेत्रों में किए गए उत्कृष्ट कार्य के लिए मध्यप्रदेश को प्रथम पुरस्कार दिया गया। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने राष्ट्रीय पंचायत दिवस पर मध्यप्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव को यह पुरस्कार प्रदान किया। इस खबर को 'सम्मान स्तंभ' में प्रकाशित किया गया है। विगत दिनों प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और श्रीलंका के राष्ट्रपति श्री मैत्रीपाल सिरिसेना ने उज्जैन में अन्तर्राष्ट्रीय विचार महाकुंभ में धर्म, ग्लोबल वार्मिंग, विज्ञान एवं अध्यात्म, कृषि, स्वच्छता और उद्योग जैसे 51 सूत्री सार्वभौमिक अमृत संदेश को लोकार्पित किया जिसकी जानकारी को 'विचार महाकुंभ' स्तंभ के अंतर्गत प्रकाशित किया गया है। गाँवों के सशक्तीकरण के लिए प्रदेश में संचालित ग्रामोदय से भारत उदय अभियान का मूल आधार गांधी जी का ग्राम स्वराज की कल्पना है इस पर केन्द्रित लेख को हमने 'विशेष लेख' स्तंभ में प्रकाशित किया है। ग्रामोदय से भारत उदय अभियान को सफल बनाने में प्रदेश सरकार पूर्ण रूप से जुटी है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के साथ-साथ सभी मंत्रीगण प्रदेशभर की ग्रामसभाओं में जाकर ग्राम संसद में भाग ले रहे हैं और ग्रामीणों की समस्याओं का तुरंत निदान कर रहे हैं इस जानकारी को 'ग्रामोदय : ग्राम संसद' स्तंभ में प्रकाशित किया गया है। प्रदेश सरकार की फ्लैगशिप योजना मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत सागर जिले के गढ़ाकोटा में विगत दिनों सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया। इस जानकारी को 'मुख्यमंत्री कन्यादान योजना' स्तंभ में शामिल किया गया है। विगत दिनों आंध्रप्रदेश के विजयवाड़ा में पांचवीं अनुसूची के क्षेत्रों के विकास में महिला सरपंचों की भूमिका पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित हुआ जिसमें प्रदेश के 10 जिलों की एक सौ सात आदिवासी महिला सरपंचों ने हिस्सा लिया। इस जानकारी को 'ग्रामोदय : महिला सशक्तीकरण' स्तंभ में प्रकाशित किया गया है। खास खबरें स्तंभ में हमने प्रदेश में ग्रामोदय से भारत उदय अभियान की समीक्षा का समाचार प्रकाशित किया है। मध्यप्रदेश के साथ-साथ देश के कई राज्य भीषण सूखे की स्थिति का सामना कर रहे हैं। ऐसे में देवास जिले के ग्राम पंचायत गोरवा में जल संरक्षण अभियान एक आदर्श उदाहरण बन गया है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में इस जल संरक्षण मॉडल का उल्लेख भी किया है। इस जानकारी को 'अच्छी पहल' स्तंभ में शामिल किया गया है। 'सिंहस्थ:विशेष' स्तंभ में सिंहस्थ-2016 से संबंधित समाचारों को प्रकाशित किया गया है। और अंत में 'पंचायत गजट' स्तंभ में हमने प्रदेश के जिला पंचायत अध्यक्षों को निज सहायक की सुविधा मिलेगी इससे संबंधित राज्य शासन के आदेश का प्रकाशन किया है।

इस अंक में बस इतना ही। हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा।

(संतोष मिश्र)
आयुक्त पंचायत राज

डॉ. अम्बेडकर की 125वीं जयंती पर 'ग्रामोदय से भारत उदय अभियान' का शुभारंभ

विकास के संसाधनों को गांव की ओर मोड़ना होगा

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 14 अप्रैल को डॉ. अम्बेडकर की जन्म-भूमि महू (अम्बेडकर नगर) में बाबा साहेब की 125वीं जयंती पर 'ग्रामोदय से भारत उदय' अभियान का शुभारंभ किया।

इस अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि भारत रत्न बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर द्वारा देश को सुदृढ़ बनाने के लिये संविधान में की गई अपेक्षाओं और महात्मा गाँधी के ग्राम स्वराज को साकार करने का काम अधूरा है। इसे पूरा करने के लिये विकास के सभी स्रोतों और संसाधनों को गाँव की ओर मोड़ने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि विकास के लिये टुकड़ों में काम करने से बात नहीं बनेगी।

अपने संबोधन में श्री मोदी ने किसानों की आय दोगुनी करने के संदर्भ में कहा कि किसान कुछ नहीं माँगता। अगर उसे पानी मिल जाये, तो मिट्टी से सोना बना सकता है। यदि दूसरों का पेट भर जाये तो किसान को सबसे बड़ा संतोष होता है।

उन्होंने कहा कि वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का संकल्प लिया गया है। यह कठिन काम है, लेकिन पूरा करना है। साथ ही प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान को किसानों की आय दोगुनी करने का रोडमैप बनाने के लिये बधाई दी। प्रधानमंत्री ने अन्य राज्यों से भी अपेक्षा की कि वे भी अपने संसाधनों के अनुरूप कार्य-योजना बनायें। जब तक गाँव की खरीद करने की क्षमता नहीं बढ़ेगी तब तक शहरी अर्थ-व्यवस्था भी नहीं बढ़ेगी।

श्री मोदी ने संबोधित करते हुये कहा कि मैं बाबा साहेब की स्मृति को नमन करने आया हूँ। पहले भी आया था, लेकिन तब से अब में जमीन-आसमान का फर्क है। उन्होंने मध्यप्रदेश की श्री शिवराज सिंह चौहान सरकार को बाबा साहेब के जन्म-स्थान का भव्य और गरिमापूर्ण विकास करने के लिये बधाई दी।

संबोधित करते हुये श्री मोदी ने कहा कि आजादी के साठ साल बाद भी ग्रामीण भारत में जो परिवर्तन आना चाहिये था वह नहीं आया। अभी बहुत कुछ करना बाकी है। उन्होंने कहा कि भारत के विकास के लिये केवल कुछ शहरों और कुछ उद्योगों के विकास से काम नहीं चलेगा। गाँव के निरंतर और स्थाई विकास के लिये गाँव को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इस साल के केन्द्रीय बजट में गाँव और खेती के विकास पर पूरा जोर दिया गया है। किसानों में नया जोश और ऊर्जा भरने पर ध्यान दिया गया है।

श्री मोदी ने कहा कि बाबा साहेब एक व्यक्ति नहीं बल्कि संकल्प का दूसरा नाम थे। वे सिर्फ जीवन नहीं जीते थे, वे संघर्ष में उसे जोत देते थे। उन्होंने समाज के वंचित वर्ग को मान-सम्मान और गरिमापूर्ण जीवन दिया। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब के पास इतना ज्ञान और शिक्षा थी कि वे अपने अच्छे जीवन के लिये कुछ भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने सब कुछ छोड़कर कमजोर वर्ग को नया जीवन देने के लिये अपना जीवन खपा दिया।

साथ ही प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि उनके प्रधानमंत्री बनने का श्रेय बाबा साहेब को जाता है। बाबा साहेब पर राजनीति करने वालों ने समाज को बाँटने के सिवाय कुछ नहीं किया। बाबा साहेब ने हर पल संघर्ष किया। उनके द्वारा बनाये गये संविधान से उनकी महानता स्पष्ट होती है। इसीलिये उनके चरणों में बैठकर अच्छे काम करने का इरादा रखते हैं।

संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी गाँवों में विद्युत सुविधा 1000 से भी कम दिन में पहुँचा दी जायेगी। उन्होंने कहा कि आजादी के 70 वर्ष होने आ रहे हैं। ऐसे में एक भी गाँव विद्युतविहीन रहे, तो यह दुर्भाग्यपूर्ण होगा।

उन्होंने कहा कि केन्द्र की वर्तमान सरकार जनता को हिसाब देने वाली सरकार है। जनता के सपनों और अपेक्षाओं को पूरा करने के लिये तेज गति से काम करने वाली सरकार है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि बाबा साहेब अंबेडकर ने कहा था शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। आर्थिक समृद्धि, सामाजिक अधिकार सम्पन्नता और प्रौद्योगिकी से समृद्धि पर उनका विश्वास था। उनके इसी सपने को नये युग में साकार करने का प्रयास कर रहे हैं। इस अवसर पर बाबा साहेब को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम गाँव की ओर चलें। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार से प्रत्येक गाँव को हर साल 75 लाख रुपये विकास कार्यों के लिये मिलते हैं। गाँव का कायापलट करने के लिये यह काफी हैं। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत में विकास की चेतना जगाये रखना और उन्हें सशक्त बनाना जरूरी है। बाबा साहेब की प्रेरणा से यह कार्य संभव है।

प्रधानमंत्री ने 'ग्रामोदय से भारत उदय' अभियान की चर्चा करते हुए कहा कि जो लोग गरीबों के मसीहा कहलाते थे उन्होंने ऐसा काम क्यों नहीं किया। वंचित वर्गों के कल्याण का काम निरंतर चलना चाहिए। उन्होंने बताया कि 90 लाख परिवारों ने गरीब परिवारों के हित में गैस सब्सिडी त्याग दी है। एक साल में देश के इतिहास में सर्वाधिक एक करोड़ परिवारों को गैस कनेक्शन दिये गये। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगले तीन साल में 5 करोड़ परिवारों को और गैस कनेक्शन दिये जायेंगे। उन्होंने कहा कि गरीब परिवार चिट फंड जैसी कम्पनियों के पास जाने पर मजबूर होते हैं। प्रधानमंत्री जन-धन योजना से अब सभी गरीब परिवार वित्तीय समावेशन की राष्ट्रीय धारा से जुड़ गये हैं। उन्हें आर्थिक सुरक्षा मिल गयी है। गरीबों को साथ लेकर ही भारत विकास कर सकता है।

साथ ही उन्होंने कहा कि भारत को तेज गति से विकास करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब की स्मृति से जुड़े पाँच स्थलों को पंच तीर्थ के रूप में विकसित किया गया है। यह श्रद्धा और विश्वास का विषय है। बाबा साहेब ने सामाजिक एकता, न्याय, समरसता और उच्च मूल्य सिखाये हैं। बाबा साहेब के चरणों में बैठकर अच्छे कार्य करने पर गर्व है।

उन्होंने बाबा साहेब के अलीपुर बंगले को स्मारक बनाने का संदर्भ देते हुए कहा कि जिन लोगों ने ऐसा नहीं किया, उन्हें परेशान होने की बजाय पश्चाताप करना चाहिए।
श्री मोदी ने गाँववासियों से अपील की कि वे परिवर्तन में भागीदार बनें और सरकार की योजनाओं का पूरा उपयोग करें। श्री मोदी ने 'जय भीम' के उद्घोष के साथ अपने भाषण का समापन किया। अम्बेडकर मेमोरियल सोसायटी इंदौर के अध्यक्ष भन्ते संघशील ने प्रधानमंत्री को धम्म पद पुस्तक भेंट की। उन्होंने इंदौर जिले को खुले में शौच जाने से पूरी तरह मुक्त होने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक जिला अब इस दिशा में प्रयास करेगा।

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान

इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि श्री मोदी भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं, जो बाबा साहेब के स्मारक पर श्रद्धा-सुमन अर्पित करने आये हैं। मध्यप्रदेश के नागरिकों को गर्व है कि बाबा साहेब ने इस भूमि पर जन्म लिया। श्री चौहान ने बाबा साहेब से जुड़े पाँच स्थानों को पंच तीर्थ के रूप में विकसित करने के लिये प्रधानमंत्री का प्रदेश के लोगों की ओर से आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि पहले की सरकारें यह नहीं कर पायीं। महू में पहले श्रद्धालुओं को परेशानियों का सामना करना पड़ता था। तत्कालीन राज्य सरकार ने 1991 में स्मारक बनाने का काम शुरू किया था। आज यह काम पूरा हो गया है।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिये लागू की गई कल्याणकारी और नवाचारी योजनाओं की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अब आवासहीन परिवारों को आवास की सुविधा मिलेगी। बाबा साहेब का सपना था कि समाज शिक्षित बने। इसी पर आगे बढ़ते हुए प्रदेश में शैक्षणिक सुविधाओं को बढ़ाया गया है। फलस्वरूप पिछले साल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के 117 विद्यार्थियों को आईआईटी और आईआईएम जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में दाखिला मिला। इन विद्यार्थियों की शैक्षणिक फीस भी सरकार दे रही है। इसी प्रकार इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज जाने वाले विद्यार्थियों की फीस भी सरकार भरेगी। उच्च अध्ययन के लिये विदेश जाने वाले बच्चों को भी राज्य सरकार भरपूर सहायता देगी।

इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री को 'ग्रामोदय से भारत उदय' अभियान का ध्वज भेंट कर अभियान का शुभारंभ किया। यह ध्वज सभी ग्राम पंचायतों में जायेगा।

ग्रामीण विकास में श्रेष्ठ कार्यों के लिये

मध्यप्रदेश को प्रथम पुरस्कार

मध्यप्रदेश के लिये यह गौरव की बात है कि राष्ट्रीय पंचायत दिवस 24 अप्रैल को पेसा एक्ट के सफल क्रियान्वयन के लिये प्रदेश को सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने झारखण्ड के जमशेदपुर में आयोजित राष्ट्रीय कार्यक्रम में प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव को यह पुरस्कार प्रदान किया।

यह पुरस्कार प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्रों में किये गये उत्कृष्ट कार्य और संवैधानिक उपबंधों के पालन के लिये दिया गया है। प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्रों में 20 जिले के 5211 गाँव हैं। पंचायत राज दिवस पर हुए इस सम्मेलन में झारखण्ड की राज्यपाल श्रीमती द्रोपदी मुरमू, केन्द्रीय ग्रामीण विकास, पंचायत राज, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री श्री चौधरी वीरेन्द्र सिंह, केन्द्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री सुदर्शन भगत और केन्द्रीय पंचायत राज्य मंत्री श्री निहालचंद भी उपस्थित थे।

अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत राज को मजबूत करने के लिये मध्यप्रदेश में तीन अलग-अलग आयाम में विशेष प्रबंध कर लगातार उल्लेखनीय कार्य उत्कृष्टता के साथ किये गये हैं। इनमें कोष, कार्यकलाप एवं कार्मिक प्रबंधन शामिल है। ये तीनों आयाम पंचायतों की सफलता के आधार स्तम्भ होते हैं। इन पर फोकस कर मध्यप्रदेश में ग्रामीण विकास की रणनीति बनाकर काम किये गये, जिसकी सराहना राष्ट्रीय स्तर पर हुई। इस कार्य की प्रशंसा केन्द्र सरकार द्वारा गठित विशेषज्ञों की समिति ने भी की थी। समिति ने सभी मापदण्डों पर मध्यप्रदेश को खरा पाया था। यही कारण है कि देश में मध्यप्रदेश को सर्वोच्च स्थान मिला है।

मुख्य बात यह है कि यह पुरस्कार एक सशक्त, समृद्ध, सम्पन्न और समरस भारत निर्माण के संकल्प के साथ 14 अप्रैल को आरंभ हुए ग्राम उदय से भारत उदय अभियान के राष्ट्रीय समापन अवसर पर प्राप्त हुआ। 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ग्राम उदय अभियान के शुभारंभ अवसर पर ग्राम उदय से भारत उदय के लिए राष्ट्र की जड़ों को सशक्त करने के साथ भविष्य की चुनौतियों का सामना करने का आह्वान किया था।

पेसा एक्ट क्रियान्वयन के लिए उठाए गए कदम

- मध्यप्रदेश में अनुसूचित क्षेत्र अंतर्गत कुल 20 जिले सम्मिलित हैं। इनमें 6 पूर्ण जिले तथा 14 जिले आंशिक हैं।
- पेसा अंतर्गत 89 जनपद पंचायतों तथा 5211 ग्राम पंचायतें सम्मिलित हैं।
- ग्राम क्षेत्र के भीतर के प्राकृतिक स्रोतों को, जिनके अंतर्गत भूमि, जल तथा वन आते हैं उनकी परम्परा के अनुसार और संविधान के उपबंधों के अनुरूप और तत्समय प्रवृत्त अन्य सुसंगत विधियों की भावना का सम्यक ध्यान रखते हुए ग्राम सभा द्वारा प्रबंध करना।
- अनुसूचित क्षेत्र की प्रत्येक स्तर की पंचायत का प्रमुख अर्थात सरपंच/अध्यक्ष अनुसूचित जनजाति वर्ग का होगा।
- अनुसूचित क्षेत्रों की ग्राम सभा की बैठकों में सरपंच को छोड़कर जनजाति वर्ग के अन्य किसी सदस्य द्वारा अध्यक्षता करने के प्रावधान किए गए हैं।
- व्यक्तियों की परम्पराओं तथा रूढ़ियों, उनकी सांस्कृतिक पहचान और सामुदायिक संसाधनों को तथा विवादों के निराकरण के रूढ़िगत ढंग को सुरक्षित तथा संरक्षित करने का प्रावधान है।

संशोधन

- पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम 1996 के प्रभावशील होने के बाद मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 170 ख में संशोधन किया गया है कि अनुसूचित क्षेत्र में यदि कोई ग्राम सभा यह पाती है कि जनजाति के सदस्य से भिन्न कोई व्यक्ति जनजाति वर्ग के भूमि स्वामी की भूमि अवैध रूप से कब्जे में लेता है तो उसके विधिक वारिसों को ग्राम सभा वापिस दिलायेगी।
- ऐसी भूमि वापिस दिलाने में ग्राम सभा असफल रहती है तो यह मामला उपखण्ड अधिकारी राजस्व को अग्रेषित किया जावेगा और वह तीन माह के भीतर वास्तविक वारिस को भूमि को वापिस दिलायेगा।

साहूकारी अधिनियम में संशोधन

- मध्यप्रदेश साहूकारी अधिनियम 1934 में संशोधन करते हुए साहूकारों के पंजीयन के लिए धारा 2 में जिला, जनपद एवं ग्राम पंचायतों को अपने-अपने क्षेत्रों में प्राधिकृत किया गया है।
- धारा 11-ख में संशोधन कर अनुसूचित क्षेत्रों में बिना पंजीयन एवं ग्राम सभा की सहमति के साहूकारी का कारोबार नहीं कर सकता है और यदि उक्त प्रावधान का उल्लंघन करता है तो वह 2 वर्ष तक का कारावास या रुपये 10000/- तक के जुर्माने से दण्डनीय होगा।

मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915

- मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 में इस आशय का संशोधन किया गया है कि अनुसूचित क्षेत्र में कोई भी मदिरा की नई दुकान ग्राम सभा की अनुमति के बिना नहीं खोली जायेगी।

मध्यप्रदेश में राजनीतिक नेतृत्व की दृढ़ इच्छाशक्ति और तंत्र की कार्यकुशलता का परिणाम है कि प्रदेश में पेसा एक्ट के प्रावधानों का सफल क्रियान्वयन किया गया। अनुसूचित जनजातियों की परम्परागत रूढ़ियों, पद्धतियों की जड़ों को मजबूती प्रदान करते हुए प्रावधान को लागू किया गया। प्रदेश के मुख्यमंत्री की मंशा और प्रेरणा से पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने विशेष पहल को आवश्यक समझा। पेसा एक्ट के प्रावधानों को लागू करने के लिए पहले उसे जानना, समझना जरूरी था अतः क्रियान्वयन से पूर्व प्रदेश में कार्यशाला का आयोजन कर क्रियान्वयन की एक सुनियोजित रणनीति बनाई गई और उसे अमल में लाया गया इसी के परिणामस्वरूप प्रदेश दक्षता के साथ कार्य कर देश में अव्वल रहा।

उल्लेखनीय है कि महामहिम राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 244(1) के अधीन अधिसूचना जारी कर देश के दस राज्यों आंध्रप्रदेश, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश और झारखंड के जनजाति बाहुल्य इलाकों को अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया हैं।

अनुसूचित क्षेत्रों की पंचायतों को राज्य सरकार द्वारा विशेष प्राधिकार प्रदान करने के उद्देश्य से संसद द्वारा 'पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम 1996 अधिनियमित कर लागू किया गया है। इस अधिनियम के द्वारा अनुसूचित जनजातियों की परम्पराओं रूढ़ियों, सामाजिक और धार्मिक पद्धतियों तथा सामुदायिक संपदाओं की परंपरागत पद्धतियों को संरक्षित किया गया है।

मध्यप्रदेश ने इस अधिनियम के सफल क्रियान्वयन की दृष्टि से अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम सभाओं को विशेष अधिकार प्रदान किए। ग्रामीण क्षेत्र में क्रियान्वित की जाने वाली सभी जनहितैषी योजनाओं के नियोजन में ग्राम सभा को भागीदार बनाया। हितग्राहीमूलक सभी

जनपद पंचायत डिण्डोरी को मिला पंचायत सशक्तीकरण पुरस्कार

डिण्डोरी जिले की जनपद पंचायत डिण्डोरी को ग्रामीण क्षेत्र में 8 सेवाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस के मौके पर झारखण्ड के जमशेदपुर में पुरस्कृत किया है। जनपद पंचायत अध्यक्ष श्रीमती देववती वालरे और जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री एस.के. गुप्ता ने यह पुरस्कार प्राप्त किया।

जनपद पंचायत डिण्डोरी ने स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक घर में शौचालय निर्माण के लिये विशेष अभियान चलाया। इसके लिये सुबह-शाम ग्रामीण क्षेत्र में चौपाल लगायी गयी। खुले में शौच पर रोक लगाने के लिये बच्चों, महिलाओं और पुरुषों की भागीदारी करते हुए निगरानी समिति बनायी गयी है। निगरानी समिति के सदस्यों ने रैली निकालकर लोगों में जागरूकता लाने के लिये नारे और लोक-गीत का उपयोग किया। ग्रामीणजन को स्वच्छता की शपथ दिलवायी गयी। स्कूलों में भी शौचालयों का निर्माण किया गया। सभी ग्राम पंचायतों में स्वच्छ जल का प्रबंध किया गया। पर्याप्त संख्या में स्टॉप-डेम, तालाब और कंटूर-ट्रंच का निर्माण किया गया। सभी ग्राम पंचायत में स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था की गयी। जनपद पंचायतों डिण्डोरी में प्राकृतिक संसाधनों के बेहतर प्रबंधन के लिये विशेष प्रयास किये गये। महिलाओं, अनुसूचित-जाति, जनजाति, दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिकों को सेवा दिलवाये जाने के लिये शिविर लगाये गये। ग्रामीणों को आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण दिलवाया गया।

जनपद पंचायत में राजस्व आय बढ़ाने के लिये दुकानों का निर्माण एवं मछली-पालन के लिये तालाबों को पट्टे पर दिये जाने के विशेष प्रयास किये गये। जनपद पंचायत में निर्धन परिवारों की कन्याओं के विवाह के लिये मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में सामूहिक विवाह के कार्यक्रम भी व्यापक स्तर पर आयोजित किये गये।

योजनाओं के अंतर्गत हितग्राही चयन के अधिकार ग्राम सभा को प्रदान किए। ग्राम सभा क्षेत्र अंतर्गत संपादित सभी निर्माण एवं विकास कार्यों के सोशल ऑडिट के अधिकार ग्राम सभा को प्रदत्त किए गए हैं। ग्राम सभा क्षेत्र की गौण खनिजों के खनन संबंधी पट्टे देने के पूर्व ग्राम सभा की सहमति को प्राथमिकता देने का प्रावधान किया गया है। ग्राम सभा की सहमति के बिना अनुसूचित क्षेत्र में कोई नई मदिरा की दुकान नहीं खोली जाएगी। इसी प्रकार ग्राम सभा की सहमति के बगैर कोई व्यक्ति अनुसूचित क्षेत्र में साहूकारी का व्यवसाय नहीं कर सकता है। पेसा एक्ट के इन सभी प्रावधानों का देश के अन्य राज्यों की तुलना में मध्यप्रदेश में सफल क्रियान्वयन हुआ है और इन्हीं विशेष उपलब्धियों के लिये भारत सरकार द्वारा मध्यप्रदेश को पुरस्कृत किया गया है।

● रीमा राय

अंतर्राष्ट्रीय विचार महाकुंभ

प्रधानमंत्री और श्रीलंका के राष्ट्रपति द्वारा सिंहस्थ सार्वभौम अमृत संदेश विश्व को समर्पित

भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और श्रीलंका के राष्ट्रपति श्री मैत्रीपाल सिरिसेना ने 14 मई को उज्जैन (निनोरा) में 51 सूत्री सिंहस्थ-2016 सार्वभौमिक अमृत संदेश को समाज और विश्व को समर्पित किया। इस संदेश में विश्वभर से आये विद्वानों के विचार-विमर्श के बाद बनाये 51 मार्गदर्शी बिन्दु हैं।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और श्रीलंका के राष्ट्रपति श्री मैत्रीपाल सिरिसेना ने निनोरा-उज्जैन में अंतर्राष्ट्रीय विचार महाकुंभ के समापन सत्र में सिंहस्थ महाकुंभ 2016 में आये सभी अखाड़ों के संतों, महंतों और संत समुदाय के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में 51 सूत्री सिंहस्थ 2016 सार्वभौमिक अमृत संदेश को समाज और विश्व को समर्पित किया।

14 मई को हुये समारोह में लोकार्पित सार्वभौम संदेश में मूल्य आधारित जीवन, मानव-कल्याण के लिये धर्म, ग्लोबल वार्मिंग एवं जलवायु परिवर्तन, विज्ञान एवं अध्यात्म, महिला सशक्तीकरण, कृषि, स्वच्छता, कुटीर उद्योग जैसे विषयों पर देश और विश्वभर से आये विद्वानों के विचार-विमर्श के बाद बनाये 51 मार्गदर्शी बिन्दु हैं।

इस अवसर पर संबोधित करते हुये श्री मोदी ने कहा कि सभी संत अपनी विचार परंपरा में हर वर्ष एक सप्ताह का विचार महाकुंभ आयोजित कर समाज को दिशा दें। उन्होंने कहा कि आज विश्व, ग्लोबल वार्मिंग और आतंकवाद दो बड़ी समस्याओं से जूझ रहा है। इन समस्याओं से निपटने के लिये जीवन मूल्यों को स्वीकार करने की जरूरत है।

कुंभ के दौरान संत और समाजवेत्ता समाज की चिंता करते थे और भविष्य के लिये नई विधाओं का अन्वेषण करते थे। कुंभ के माध्यम से अगले बारह साल के लिये समाज की दिशा और कार्य-योजना तय होती थी। हर तीन साल के बाद इसकी समीक्षा होती थी। कुंभ एक अद्‌भुत सामाजिक रचना थी पर धीरे-धीरे इस परम्परा के प्राण खो गये। उज्जैन के इस कुंभ से एक नया प्रयास प्रारंभ हुआ और सदियों पुरानी व्यवस्था का आधुनिकीकरण किया गया।

श्री मोदी ने कहा कि हमें भारतीय मूल्यों और ज्ञान को वैज्ञानिक आधार पर दुनिया के

सामने रखना होगा और उनके आधार पर समस्याओं का समाधान ढूँढ़ना होगा। मानव-कल्याण के लिये हर कुंभ मेले में विचार-मंथन की परंपरा आगे बढ़ाते हुए समाज के लिये मार्गदर्शी अमृत बिन्दु निकाले जायें। उन्होंने कहा कि भारत आत्मा के अमरत्व से जुड़ी परम्परा को मानने वाला देश है। कुम्भ की महान परम्परा सामाजिक संदर्भों में विचार से जुड़ी सांस्कृतिक परम्परा है। यह विशाल भारत को अपने में समेटने का प्रयास है। उन्होंने कहा कि कुंभ में बिना निमंत्रण के विशाल संख्या में श्रद्धालु आते हैं। यह प्रबंधन की सबसे बड़ी घटना है। कुंभ मेले के प्रबंधन को दुनिया के सामने अध्ययन के लिये प्रस्तुत करना चाहिए। हमारे चुनाव भी दुनिया के लिये प्रबंधन का बहुत बड़ा उदाहरण है।

साथ ही प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि समाज के लिये निःस्वार्थ भाव से काम करने वाले संत, वैज्ञानिक, किसान, मजदूर और नागरिक एक दिशा में चलकर बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। यह अमृत बिन्दु भारत और वैश्विक जन-समूह को आने वाले समय में दिशा देंगे। भारतीय मूल चिंतन सबके कल्याण का है। हमारे यहाँ दूसरों के लिये त्याग को आनंद से जोड़ा है। पूर्व प्रधानमंत्री श्री लालबहादुर शास्त्री ने देश से सप्ताह में एक दिन उपवास का आग्रह किया और जनता ने उसे करके दिखाया। ऐसा ही एक विषय मैंने जनता के सामने रखा कि रसोई गैस की सब्सिडी छोड़ दें और देश के एक करोड़ से ज्यादा परिवारों ने सब्सिडी छोड़ दी। इससे अगले तीन साल में पाँच करोड़ गरीब परिवारों को धुँए वाले चूल्हे से मुक्ति मिलेगी और जंगल बचेंगे।

प्रधानमंत्री ने साथ ही कहा कि हमारी परंपरा में ज्ञान को अजर-अमर माना गया है। विश्व में जो भी श्रेष्ठ है उसे लेना और समाहित करना हमारी आदत है। हम ऐसे समाज के लोग हैं जहाँ विविधताएँ हैं। हमें आंतरिक विवादों के प्रबंधन में महारत हासिल है। भारत हठवादिता से नहीं बल्कि दर्शन से जुड़ा देश है। हमारा दर्शन जीवन के लिये जीने की प्रेरणा देता है। आज भारत के पारिवारिक जीवन मूल्यों को पूरा विश्व स्वीकार कर रहा है। हमारे सामने चुनौती है कि समय की कसौटी पर खरे उतरें। जीवन मूल्यों के प्रति समाज को जागरूक करें। आज समय बदल चुका है। विस्तारवाद समस्याओं का हल नहीं है। हमें जीवन मूल्यों को स्वीकार करना होगा। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से बचने के लिये भारत के प्रकृति प्रेम के मूल्यों को विश्व के समक्ष रखना होगा। उन्होंने कहा कि जो बातें काल ब्राह्य हैं उन्हें छोड़ना होगा। हमारा वैश्विक दायित्व बनता है कि लोगों को आपस में जोड़ने के विशिष्ट गुण को बढ़ाया जाये।

इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने उज्जैन में कुंभ के आयोजन से जुड़े सभी नागरिकों और सरकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को और संकट के समय श्रद्धालुओं की मदद के लिये उज्जैन के नागरिकों को धन्यवाद दिया।

इसी तारतम्य में श्रीलंका के राष्ट्रपति श्री मैत्रीपाल सिरिसेना ने विचार कुंभ में आमंत्रित करने के लिये प्रधानमंत्री श्री मोदी और मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान को धन्यवाद दिया। अनागरिक धम्मपाल की प्रतिमा के अनावरण का संदर्भ देते हुए उन्होंने कहा कि भारत और श्रीलंका के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंध हैं। उन्होंने कहा कि धार्मिक और सांस्कृतिक संबंध और उनसे जुड़े विषयों पर दोनों देशों के बीच गहरी समझ है।

सार्वभौम संदेश कार्यक्रम के उद्बोधन में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कुंभ की विचार-मंथन की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए पिछले दो वर्ष से विश्व की ज्वलंत समस्याओं पर देश-विदेश के विद्वानों

विश्व स्तरीय क्राउड मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का आधार बनेगा सिंहस्थ

भारत में नीदरलैंड के राजदूत श्री एचई अलफॉन्सस ने कहा है कि विश्व में एक अवसर पर एक स्थान पर इतनी अधिक भीड़ एक-साथ कहीं एकत्र नहीं होती जितनी कि सिंहस्थ पर्व पर उज्जैन में होती है। इसलिए उज्जैन को भीड़ प्रबंधन के अध्ययन के लिए चुना गया है। इस अध्ययन, विश्लेषण तथा शोध के बाद क्राउड मैनेजमेंट सिस्टम पर सॉफ्टवेयर विकसित किया जायेगा। राजदूत श्री अलफॉन्सस ने यह जानकारी उज्जैन में दी। उन्होंने बताया कि नीदरलैण्ड, रशिया तथा सिंगापुर के विश्वविद्यालय और भारत सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इंडियन इन्स्टीट्यूट ऑफ साइंस, आई.आई.टी. कॉनपुर और भारतीय औद्योगिक घरानों और स्टार्टअप कम्पनी द्वारा संयुक्त रूप से भीड़ नियंत्रण अध्ययन का प्रोजेक्ट आरम्भ किया गया है। भारत, नीदरलैंड संयुक्त शोध शिविर दत्त अखाड़ा क्षेत्र में स्थापित किया गया है। भीड़ के मनोविज्ञान, व्यवहार सहित गतिशीलता और ठहराव के कारण सुरक्षा भावना, व्यवस्था से सहयोग आदि विषय पर डाटा एकत्र किया जा रहा है। इस अध्ययन में जीपीएस, ड्रोन, लोकेट सेन्सर, श्रेष्ठतम कैमरों आदि तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। अध्ययन का उद्देश्य आपदा प्रबंधन के लिए ऐसी गाईडलाइन तथा सॉफ्टवेयर विकसित करना है जिसका उपयोग संपूर्ण विश्व में अलग-अलग प्रयोजनों जैसे ओलम्पिक, बड़े सांस्कृतिक आयोजनों और संकट के समय भीड़ प्रबंधन के लिए किया जा सकता है। उज्जैन सिंहस्थ के संबंध में अपने अनुभव साझा करते हुए श्री अलफॉन्सस ने कहा कि अधोसंरचना विकास, साफ-सफाई व्यवस्था, आई.टी. का उपयोग और लोगों का व्यवहार स्मार्ट सिटी की अवधारणा के रोल मॉडल को प्रस्तुत करता है।

अंतर्राष्ट्रीय विचार महाकुंभ

और संतों का विचार-मंथन चला। समस्याओं के संभावित समाधान निकाले गये और 51 बिन्दुओं के अमृत संदेश का उद्‍घोष हुआ। उन्होंने कहा कि सिंहस्थ की घोषणा के पालन की शुरुआत मध्यप्रदेश से होगी। राज्य सरकार आनंद मंत्रालय का गठन करने जा रही है। इसके माध्यम से प्रसन्न रहने के आध्यात्मिक तरीकों पर विचार किया जायेगा।

श्री चौहान ने साथ ही यह भी कहा कि सबसे बड़ी समस्या जलवायु परिवर्तन की है। इससे नदियाँ सूख रही हैं। इस दिशा में पहल करते हुए राज्य सरकार नर्मदा और क्षिप्रा नदियों को बचाने का काम शुरू करेगी।

संतों की उपस्थिति में देवउठनी ग्यारस से अमरकंटक से नदियों के जन-जागरण का विशाल अभियान शुरू होगा। जन सहयोग से पेड़ लगाने की शुरुआत होगी। किसानों को फलदार पेड़ लगाने के लिये प्रोत्साहित किया जायेगा। जब तक किसानों के खेतों में पेड़ तीन साल के नहीं हो जाते तब तक की अवधि का फसल मुआवजा उन्हें राज्य सरकार देगी। क्षिप्रा के किनारे भी पेड़ लगाने की शुरुआत की जायेगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि खेती की दिशा बदलते हुए सरकार ऋषि खेती को बढ़ावा देगी। सभी विकासखंड में आदर्श कृषि प्रक्षेत्र बनेंगे। प्रदेश को जैविक खेती का प्रदेश बनाया जायेगा। उन्होंने कहा कि स्वच्छता को सामाजिक आंदोलन बनाने का अभियान निरंतर जारी रहेगा। ऐसे लोगों को स्थानीय चुनावों में भाग लेने से अयोग्य ठहराया जायेगा, जिनके यहाँ शौचालय नहीं है। इसके लिये कानून बनाया जायेगा। जल-संरचनाओं को फिर से जीवित किया जायेगा।

संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि प्राथमिक और माध्यमिक कक्षाओं के पाठ्यक्रम में बदलाव करते हुए नैतिक शिक्षा को शामिल किया जायेगा। गीता, उपनिषद और अन्य धार्मिक ग्रंथों की नैतिक शिक्षाओं को शामिल किया जायेगा। विज्ञापनों में नारी के वस्तु के रूप में प्रदर्शन पर रोक लगाने के लिये कानून बनाया जायेगा। उन्होंने कहा कि नारी की गरिमा एवं सम्मान समाज का कर्तव्य है। लघु और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जायेगा। उन्होंने कहा कि सिंहस्थ घोषणा-पत्र को संयुक्त राष्ट्र संघ एवं सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भेजा जायेगा।

आयोजन समिति के अध्यक्ष एवं राज्य सभा सदस्य श्री अनिल माधव दवे ने समापन सत्र का संचालन किया। श्री दवे ने तीन दिन में हुए विचार-विमर्श की जानकारी देते हुए बताया कि इस विचार-मंथन में प्रमुख देशों का प्रतिनिधित्व रहा।

कार्यक्रम में गोवा की राज्यपाल श्रीमती मृदुला सिन्हा, केन्द्रीय इस्पात मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, केन्द्रीय सामाजिक न्याय मंत्री श्री थावरचंद गेहलोत, सद्‍गुरू श्री जग्गी वासुदेव, जूना अखाड़ा महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरि, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह, झारखंड के मुख्यमंत्री श्री रघुवर प्रसाद, श्रीलंका के विपक्ष के नेता श्री आर. सम्पंथान, बंगलादेश के सांसद श्री साघन चन्द्र मजूमदार, प्रदेश के संस्कृति राज्यमंत्री श्री सुरेन्द्र पटवा, बड़ी संख्या में देश-विदेश से आये विषय-विशेषज्ञ, विचारक और संत समाज के लोग उपस्थित थे।

अंतर्राष्ट्रीय विचार महाकुंभ

सिंहस्थ 2016 विक्रम संवत् 2073

सिंहस्थ 2016 का सार्वभौम अमृत संदेश

यह कि भारत के प्राचीन नगर उज्जैन में वैदिक काल से निरंतर बारह वर्ष के अंतराल से आयोजित सिंहस्थ के पवित्र कुंभ मेले के अवसर पर;

इस बात को रेखांकित करते हुए कि अत्यंत श्रद्धा और आस्था का यह आध्यात्मिक अवसर परंपरागत रूप से प्रज्ञावान संतों और चिंतकों को समकालीन सामयिक आध्यात्मिक एवं भौतिक विचारणीय विषयों के संबंध में संवाद और विमर्श का मंच उपलब्ध कराता रहा है;

इस बात से आश्वस्त होते हुए कि इस महान परंपरा को निरंतर रखने की आवश्यकता है, मध्यप्रदेश शासन ने सिंहस्थ 2016 के दौरान 12 से 14 मई के बीच निनोरा, उज्जैन में सम्यक जीवन-शैली पर अंतर्राष्ट्रीय विचार महाकुंभ का आयोजन किया है;

मूल्याधारित जीवन, मानव-कल्याण के लिए धर्म, ग्लोबल वार्मिंग एवं जलवायु परिवर्तन, विज्ञान एवं अध्यात्म, महिला सशक्तीकरण, कृषि की ऋषि परंपरा, स्वच्छता एवं पवित्रता, कुटीर एवं ग्रामोद्योग विषयों पर भारत एवं विश्व भर के विभिन्न देशों से आए **विद्वानों के विमर्शों से प्रेरित होकर:**

इस बात से सहमति व्यक्त करते हुए कि यह तात्विक रूप से आवश्यक है कि मानव ऐसा सम्यक जीवन बिताए जिससे वह अपनी पूर्ण संभावनाओं को साकार कर सके;

प्रत्येक मानव एवं संस्कृति की विशेषता का सम्मान करते हुए, यह अनुभव किया गया कि सम्यक जीवन के विभिन्न आयामों को समस्त मानवता के लाभ के लिए स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त किया जाए;

अतः, यह **विचार महाकुंभ**, परिपूर्ण मानव जीवन के लिए प्रासंगिक मार्गदर्शी सिद्धांतों को **सिंहस्थ 2016 के सार्वभौम अमृत संदेश** के रूप में घोषित करता है कि :-

(1) मनुष्य का अस्तित्व मात्र भौतिक नहीं है। उसके चैतन्य और संवेदन के आयाम अनंत हैं। यह चेतना समस्त चराचर में व्याप्त है। यह सत्य जीवन में मूल्यों का आधारभूत प्रेरक है।

(2) संपूर्ण मानव जाति एक परिवार है। अतः सहयोग और अंतर्निर्भरता के विभिन्न रूपों को अधिकतम प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।

(3) विकास का लक्ष्य सभी के सुख, स्वास्थ्य और कल्याण को सुनिश्चित करना है। जीवन में मूल्य के साथ जीवन के मूल्य का उतना ही सम्मान करना जरूरी है।

(4) शिक्षा में मूल्यों के शिक्षण, व्यवहार एवं विकास का नियमित पाठ्यक्रम शामिल किया जाए, ताकि कम उम्र से ही बच्चों में उनका प्रस्फुटन हो सके। इस पाठ्यक्रम को अन्य विषयों की तरह समान महत्व दिया जाना चाहिए। यह पाठ्यक्रम ऐसे आरंभिक प्लेटफार्म की तरह हो जिसके आस-

पास शिक्षा का संपूर्ण पाठ्यक्रम विकसित किया जा सके।

(5) अस्वस्थ प्रतिस्पर्धात्मकता के स्थान पर सामाजिकता, अंतर्निर्भरता करुणा, मैत्री, दया, विनम्रता, आदर, धैर्य, विश्वास, कृतज्ञता, पारदर्शिता, सहानुभूति और सहयोग जैसे मूल्यों को बढ़ाने के लिए शिक्षा की पद्धतियों में यथोचित परिवर्तन किया जाए।

(6) मूल्यान्वेषण सिर्फ निजी विकास के लिए नहीं बल्कि समाज को एक व्यवस्था देने, संबंधों को संतुलित करने और जीवन प्रतिमानों का निर्माण करने के लिए जरूरी है।

(7) शुचिता, पारदर्शिता और जवाबदेही सार्वजनिक जीवन की कसौटी होना चाहिए।

(8) सत्य तक पहुँचने के अनेक मार्ग हैं, किन्तु सत्य एक ही है। विविधता में एकता स्थापित करने के लिए यह समझ अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

(9) सर्वधर्म समादर की भावना विकसित करने के लिये शिक्षा में उपयुक्त पाठ्यक्रम सम्मिलित किये जायें।

(10) सृष्टि एक ही चेतना का विस्तार है और मानव उसी का अंश है। अतः समस्त जीवों के प्रति दया, प्रेम व करुणा आधारित व्यवस्थाएँ निर्मित की जानी चाहिए। धर्म मनुष्य की आत्मोन्नति का मार्ग तथा मानव-कल्याण का साधन है। धर्म जहाँ हमें प्रेम, सहयोग, सामन्जस्य के पाठ के माध्यम से एक सूत्र में बाँधता है, वहीं विस्तारवादी उद्देश्यों के लिए किये गये उसके दुरुपयोग से विश्वबंधुता का हनन होता है।

(11) धर्म यह सीख देता है कि जो स्वयं को अच्छा न लगे, वह दूसरों के लिए भी नहीं करना चाहिए। जियो और जीने दो का विचार हमारे सामाजिक व्यवहार का मार्गदर्शी सिद्धांत होना चाहिए।

(12) धर्म जोड़ने वाली शक्ति है। अतः धर्म के नाम पर की जा रही सभी प्रकार की हिंसा का विरोध विश्व भर के समस्त धर्मों, पंथों, संप्रदायों और विश्वास-पद्धतियों के प्रमुखों द्वारा किया जाना चाहिए।

(13) पृथ्वी पर पर्यावरणीय संकट का समाधान सिर्फ प्रकृति के साथ आत्मीयता से प्राप्त होगा।

(14) देशज ज्ञान के विविध क्षेत्रों, जैसे कृषि, वानिकी, पारंपरिक चिकित्सा, जैव विविधता संरक्षण, संसाधन प्रबंधन और प्राकृतिक आपदा में महत्वपूर्ण सूचना स्रोत के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए।

(15) पारिस्थितिकी की रक्षा के लिए अत्यधिक उपभोक्तावाद पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है। प्राकृतिक संसाधनों के अविवेकपूर्ण शोषण ने अनेक प्राकृतिक विपदाओं को जन्म दिया है। इसका संज्ञान लेते हुए ऐसी जीवन शैली एवं अर्थ-व्यवस्थाओं को विकसित करें जिनसे प्रकृति का पोषण हो।

(16) विश्व में व्याप्त भीषण जल-संकट से जीवन संकट में है। जल-संवर्धन की तकनीकों और प्रणालियों को प्रोत्साहित करने और पृथ्वी की जल-संभरता को क्षति पहुँचाने वाली प्रक्रियाओं को रोकने के कदम तत्काल उठाए जाएं।

(17) प्राचीन सभ्यता और संस्कृति वाले सामाजिक समूहों ने प्रकृति से नैसर्गिक संबंध स्थापित करने के रीति-रिवाज एवं कलाओं का विकास किया है। ऐसे मानवीय व्यवहार एवं जीवन शैली का वैज्ञानिक आधार समझकर आधुनिक जीवन में उनका अनुसरण आवश्यकतानुसार करना चाहिए।

(18) भावी पीढ़ियों के प्रति अपने दायित्वों के जवाबदेह निर्वहन के लिए यह आवश्यक है कि नीतियाँ प्राकृतिक संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के भाव से प्रेरित हों। पृथ्वी पर हरित आवरण में आ रही कमी गंभीर चिंता एवं चिंतन का विषय है। अतः पौध रोपण एवं धरती के भीतर के रूट स्टॉक के पुनर्जीवन के लिए वृहद रूप से काम किया जाना चाहिए।

(19) विज्ञान और अध्यात्म एक दूसरे के पूरक हैं। प्रकृति के भौतिक रहस्यों को जानने के लिए विज्ञान और आंतरिक रहस्यों को समझने के लिए अध्यात्म की आवश्यकता है। विज्ञान और अध्यात्म के संबंधों का संस्थागत रूप से अध्ययन आवश्यक है।

(20) मनुष्य के अनुभव भौतिक के साथ-साथ आध्यात्मिक स्तर पर भी होते हैं। भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समृद्धि अनिवार्य है, परन्तु ऐसी समृद्धि आध्यात्मिक अनुभव के बिना संतुलित जीवन का आधार नहीं बन सकती।

(21) विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी में जो संबंध है वही संबंध आध्यात्मिक उन्नति का योग एवं ध्यान के साथ है। उत्कृष्ट समाज की रचना मानव जीवन में उस व्यापक दृष्टिकोण को लाने से संभव है, जो योग के माध्यम से प्राप्त होता है।

(22) अध्यात्म की विषय-वस्तु को पाठ्यक्रमों में सरल स्वरूप में सम्मिलित करना चाहिए। विषयों के भौतिक ज्ञान के अतिरिक्त उनमें निहित प्राकृतिक नियमों एवं नैसर्गिकता की जानकारी विद्यार्थियों के मानसिक परिपक्वता का साधन बनेगी।

(23) प्रकृति के नियमों के विरुद्ध जीवन यापन करने की वर्तमान जीवन शैली से शारीरिक एवं मानसिक व्याधियों में तीव्र गति से वृद्धि हुई है। इन्हें दूर करने के लिए योग एवं आयुर्वेद की प्रणालियों एवं प्रभावों के विषय को आधुनिक चिकित्सा विज्ञान से जोड़ने संबंधी शोध को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। इससे आनंदपूर्ण जीवन के मूलभूत सिद्धांत आसानी से समझ में आ सकेंगे।

(24) स्वच्छता की किसी भी रणनीति में विभिन्न विश्वास प्रणालियों में मौजूद आंतरिक पवित्रता और बाह्य शुद्धता के प्रासंगिक सिद्धांतों का लाभ लिया जाना चाहिए। स्वच्छता को प्रशासित गतिविधि की जगह सामाजिक मूल्य के रूप में पुनर्स्थापित किया जाना चाहिए।

(25) स्वच्छता की रणनीति को मात्र व्यक्ति की आर्थिक स्थिति से जोड़कर विकसित नहीं किया जाना चाहिए।

(26) 'वेस्ट' को संसाधन की दृष्टि से देखने से भी स्वच्छता बढ़ाई जा सकती है। फसल-उर्वरीकरण में वेस्ट की भूमिका टिकाऊ कृषि की पारंपरिक प्रथाओं में शामिल रही है।

(27) नदियों का संकट सिर्फ प्रदूषण तक सीमित नहीं बल्कि अस्तित्व से जुड़ा है। नदियों का लुप्त होना इस ग्रह की पारिस्थितिकी की स्थिरता के लिए चुनौती है। नदियों के पुनर्जीवन के प्रयासों को सघन और उनके अंतर्राष्ट्रीय अनुभवों को साझा किया जाए।

(28) अनियोजित शहरीकरण ने नदियों को ड्रेनेज के रूप में इस्तेमाल किया है। नागरिकों में सरिता-संवेदनशीलता को बढ़ाने के अलावा शहरी नियोजन में उनके संरक्षण के प्रभावी प्रावधान किए जाने चाहिए।

(29) नारी के द्वारा किए जा रहे गृह कार्य का मूल्य घर के बाहर किए जाने वाले व्यावसायिक कार्य के तुल्य है। उसके गृह कार्य को सकल घरेलू उत्पाद में शामिल करने की प्रविधियाँ विकसित की जाएं।

(30) स्त्री को विज्ञापनों में वस्तु की तरह प्रस्तुत करना कानूनन निषिद्ध किया जाए।

(31) प्रत्येक स्तर पर नारी-समकक्षता-सूचकांक विकसित कर उसके आधार पर समीक्षा के मानक तय किये जाएं।

(32) समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत स्त्री रोजगार के सिलसिले में अपनाया जाए। इसके लिए नियोक्ता की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए उनसे विमर्श का एक अभियान शुरू किया जाए।

(33) सभी परामर्शदात्री, नियामक, निगरानी तथा अन्य निकायों में स्त्रियों को समान रूप से प्रतिनिधित्व दिया जाये। समानता निष्पक्षता से प्राप्त नहीं की जा सकती, यह सकारात्मक हस्तक्षेप के बिना संभव नहीं है।

(34) नारी की मानवीय प्रतिष्ठा और गरिमा सार्वभौम रूप से स्वीकार्य होनी चाहिए तथा यह शासकीय नीतियों तथा योजनाओं में परिलक्षित होनी चाहिए।

(35) विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी को नारी के विरुद्ध इस्तेमाल करने के सभी संभावित तरीकों पर प्रभावी रोक होना चाहिए।

(36) महिलाओं की समस्याओं का समाधान करते समय उनके संपूर्ण जीवन-चक्र को दृष्टि में रखना आवश्यक है। संतान के सृजन और पालन के दायित्व को ध्यान में रखकर उनके पोषण, आहार, प्रजनन और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

(37) महिलाओं के प्रतिनिधित्व और आरक्षण संबंधी प्रावधानों का लाभ लोकतंत्र के सभी स्तरों पर संविधिक रूप से मिलना चाहिए।

(38) घरेलू महिलाओं के दैनंदिन जीवन क्रम को सुविधायुक्त बनाने के लिए सुसंगत अधोसंरचना में निवेश आवश्यक है ताकि वह अन्य उत्पादक कार्यों में अधिक भागीदारी कर सके।

(39) 20वीं शताब्दी से विकसित की जा रही कृषि प्रौद्योगिकियों से प्राथमिक क्षेत्र में अत्यधिक ग्रीन हाऊस गैस का उत्सर्जन होना चिन्ताजनक है। इस समस्या का समाधान आवश्यक है।

(40) भू-जल-स्तर का गिरना, मिट्टी का क्षरण और उसकी सहज उर्वरा शक्ति का नाश, रासायनिक प्रदूषण होना कृषि में अमृत-दृष्टि के अभाव का प्रतीक है। कृषि के प्रति ऐसी दृष्टि विकसित करने की आवश्यकता है, जो उसकी पुनर्रुत्पादकता को पोषित कर सके।

(41) किसानों की बीज-स्वायत्तता उनका मौलिक और अनुलंघनीय अधिकार है। इस अधिकार की सुरक्षा जैव-विविधता की भी रक्षा है।

(42) देशज गौ-वंश के संरक्षण को उसके पर्यावरण पर होने वाले सकारात्मक प्रभाव की दृष्टि से देखा जाना चाहिए।

(43) संवहनीय कृषि के लिये आधुनिक नीतियों के पुनरीक्षण की आवश्यकता है। कृषि की सुस्थिरता के लिए व्यापक वृक्षायुर्वेद, अग्निहोत्र कृषि, वैदिक खेती, सहज कृषि, प्राकृतिक खेती, जैविक खेती जैसे विकल्पों की संभावनाओं पर प्राथमिकता से शोध किया जाना आवश्यक है।

(44) सभी हितधारकों को संयुक्त रूप से कृषि की बाजार निर्भरता और ऋणोन्मुख प्रकृति के विकल्प ढूंढ़ने की पहल करना होगी। प्राकृतिक हरित खादों का अधिक प्रयोग कृषि को सुस्थिर बनाता है। पंचगव्य, जीवामृत, मटका खाद जैसी अतिरिक्त सहज तकनीकों से बेहतर परिणाम प्राप्त किये जा सकते हैं। अजैविक आदानों की तुलना में जैविक आदानों को राजकोषीय सहायता, ऋण एवं बाजार-समर्थन में प्राथमिकता मिलनी चाहिए।

(45) ऐसी पद्धतियों और कृषि आदान को हतोत्साहित करना चाहिए जो मिट्टी के स्वास्थ्य, पशुओं और वनस्पति के स्वास्थ्य, जल संतुलन और पर्या-प्रणाली पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं।

(46) शून्य बजट खेती की अवधारणा को लोकप्रिय करने की जरूरत है ताकि

न्यूनतम लागत से अधिकतम लाभ अर्जित किया जा सके।

(47) पूंजी का अधिकतम लोगों में अधिकतम प्रसार ही आर्थिक प्रजातंत्र है। कुटीर उद्योगों को आर्थिक एवं सामाजिक प्रजातंत्र के महत्वपूर्ण अंश की तरह देखा जाना चाहिए।

(48) ऐसी औद्योगिकता को प्रोत्साहित किया जाए, जिसमें कुटीर उद्योगों के वैविध्य का सम्मान हो और वे किसी असमान प्रतिस्पर्धा में खड़े न हों। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठनों से उनके संरक्षण तथा संवर्द्धन की सचेत कोशिशों का आग्रह किया जाना चाहिए।

(49) कुटीर उद्योग मास प्रोडक्शन के स्थान पर प्रोडक्शन बाय मासेस के सिद्धांत को क्रियान्वित करने का प्रबल साधन है। इसके माध्यम से समावेशित विकास के लक्ष्य को प्राप्त किया जाना संभव है।

(50) कुटीर उद्योगों के छोटे उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए ई-तकनीक पर आधारित मार्केटिंग नेटवर्क विकसित किये जाएं ताकि उनका उत्पाद विश्व भर के उपभोक्ताओं को उपलब्ध हो सकें।

(51) शिल्पी दिहाड़ी मजदूर के रूप में परिवर्तित होते जा रहे हैं। वह मात्र उद्यमी नहीं, बल्कि सृजनधर्मी कलाकार हैं। देशज संस्कृति के संवर्धन में उनके योगदान को समाज में आदर मिलना चाहिए।

इस विचार महाकुंभ का विनम्र आग्रह है कि पृथ्वी पर सम्यक और संतुलित जीवन के लिए इस संदेश में निहित मूल्यों और सिद्धातों को हर समुदाय अपने परिवेश और प्रासंगिकता के अनुरूप क्रियान्वित करने का उपक्रम करें।

आज दिनांक 14 मई, 2016, वैशाख 24, शक संवत 1938 को जारी।

वैशाख अष्टमी विक्रम संवत 2073

ग्रामोदय से भारत उदय अभियान

गांधी जी की ग्राम स्वराज अवधारणा पर आधारित ग्रामोदय

तब वे मात्र मोहनदास करमचंद गांधी थे। अभी वे महात्मा गांधी नहीं बने थे, बीसवीं सदी के दूसरे दशक में सन् 1915 में वे दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। बम्बई के बंदरगाह पर उनके स्वागत का विशाल प्रबंध था। गांधी जी गोपालकृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरू मानते थे। "गोखले जी, मैं देश सेवा के उद्देश्य से स्वदेश लौटा हूँ। मेरा मार्गदर्शन करें" - उन्होंने गोखले से कहा था। "तुम पहले देश को तो पहचानो" - गोखले ने गांधी से कहा और फिर समझाईश देते हुए कहा - "गांधी, यह देश गांवों में बसता है। भारत को समझने के लिये गांवों में जाओ," ठीक यही बात महात्मा गांधी ने सन् 1946 में अपने परम शिष्य ठाकुरदास बंग से कही थी जब उन्होंने गांधी जी से कहा - बापू अब देश आजाद होने वाले है में अमेरिका जाकर अर्थशास्त्र पढ़ना चाहता हूँ। गांधी जी बोले - अगर तुम्हें वाकई में अर्थशास्त्र का ज्ञान प्राप्त करना है तो भारत के गांवों में जाओ।

गांवों में जाकर भारत को समझने का फ़लसफा गांधी जी के मन मानस में बहुत गहरे पैठ चुका था। अफ्रीका-प्रवास से स्वदेश लौटते समय उन्होंने अपनी लंबी जलपोत-यात्रा में एक पूरा प्रपत्र ही लिख दिया था जिसका विषय था **ग्राम स्वराज**।

बम्बई से रेलयात्रा करते समय राजकोट के पहले गांधी जी से मिलने एक सज्जन आये जिनका नाम था मोतीलाल दर्जी। वे कपड़े सीने का काम करते थे। गांधी जी ने उनसे गांव का कुशल-मंगल पूछा। वे बोले - "गांधी जी! हमारे गांव में हर किसान, दर्जी, लुहार, सुनार, कुम्हार, रंगरेज, धोबी, चर्मकार, बसोड़ यानी अपना परंपरागत काम-धंधा करने वाले सब लोग, कुशल-मंगल से हैं," गांधी जी को गोखले जी याद आ गये और फिर **ग्राम स्वराज** पर लिखा अपना स्वयं का प्रपत्र जिसमें उन्होंने गांवों के गृह और कुटीर उद्योगों को न केवल पुनर्जीवित करने की बात

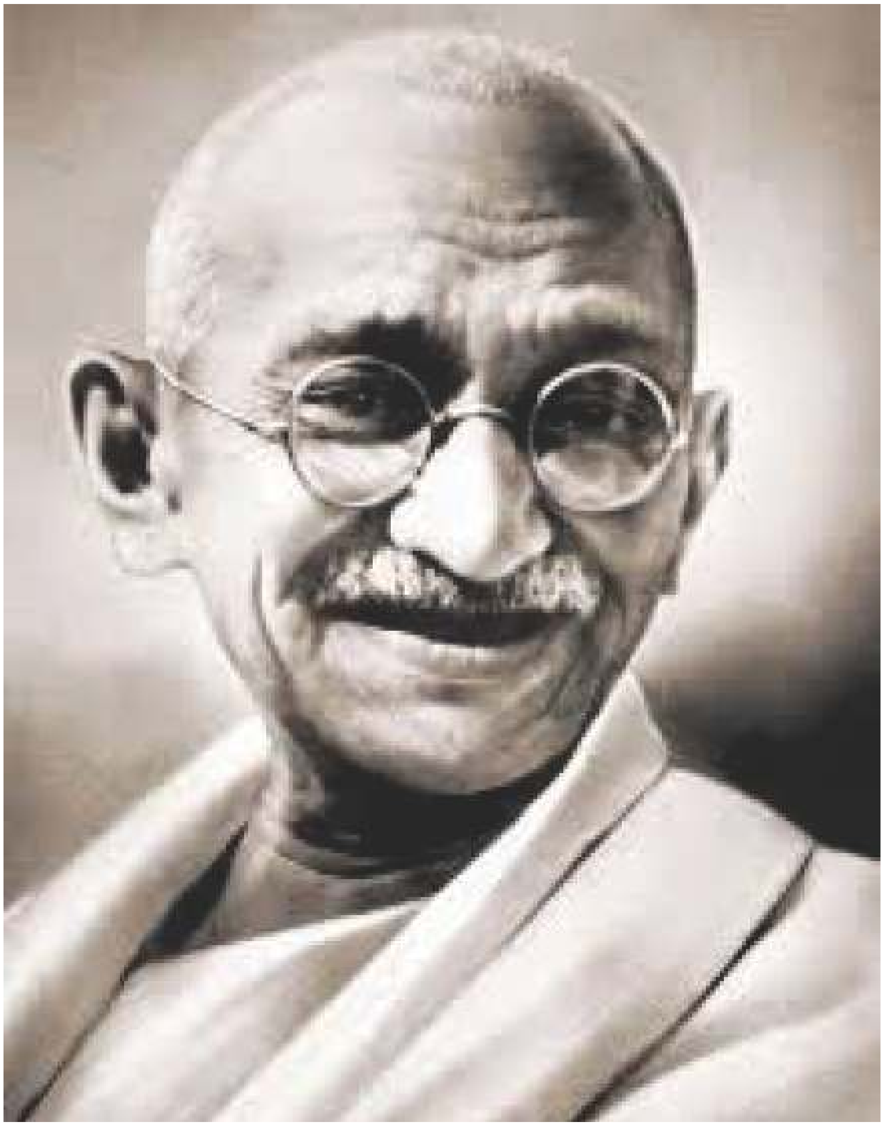

की थी बल्कि उनके विकास के लिये विद्वान का सहारा लेने का सुझाव भी दिया था। उन्होंने कहा था कि "लोगों को यह भ्रम है कि मैं मशीनरी का विरोधी हूँ। हमारा शरीर भगवत्-प्रदत्त एक जटिल मशीनरी ही तो है। उपयोगिता की दृष्टि से देखें तो भोजन के बाद दांत कुरेदने का तिनका भी तो मशीन ही है।" महात्मा गांधी से मोतीलाल दर्जी के मिलन-प्रसंग से यह स्मरण हो आया कि मध्यप्रदेश में '**ग्रामोदय से भारतोदय**' अभियान का जो कार्यक्रम 45 दिन चलाया उसमें महिला सशक्तीकरण के संदर्भ में ऐसी बहुत सी महिलायें सामने आईं जो पंच या सरपंच होने के बावजूद सिलाई-कढ़ाई (आधुनिक शब्दावली में फैशन डिजायनिंग) करके अच्छी खासी कमाई अपने ही स्वरोजगार से कर लेती हैं। अब

दर्जी, लुहार या चर्मकार कोई जाति नहीं रह गई है बल्कि रोजी-रोजगार के माध्यम और काम-धंधों के नाम हैं। ये छोटी जातियां नहीं हैं बल्कि स्वाभिमानी उद्योगी हैं। शास्त्रों के अनुसार हमारे यहां जातियां जन्मना न होकर कर्मणा थीं।

गांधी जी की धारणा थी कि जिस काम में बहुत विशेषज्ञता, ज्यादा बिजली या भारी मशीनरी नहीं लगती है और जो काम मानवश्रम या स्थानीय कला कौशल से हो सकता हो वह काम गांव में ही होना चाहिये। यदि कच्चा माल गांव का है तो फिर वहीं उसी पर आधारित मेन्यूफैक्चरिंग करके माल नगर को जाना चाहिये। माननीय नरेन्द्र मोदीजी ने इसी अवधारणा पर आधारित नारा दिया था - "फार्म टु फाइबर टु फेब्रिक टु फैशन" यानी गांव के कपास से रेशा और उससे कपड़ा और फैशन डिजाइनिंग। यह ग्रामीण आधारित आर्थिक क्रांति का मूलमंत्र है।

मध्यप्रदेश का ग्रामोदय महात्मा गांधी की ग्राम स्वराज की मूल अवधारणा से ही प्रेरित है। दिनांक 24 अप्रैल को झारखंड के जमशेदपुर में आयोजित राष्ट्रीय पंचायत दिवस के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री ने डिंडोरी, जिले की जनपद पंचायत अध्यक्ष श्रीमती देववती वालरे को जिस प्रकार सम्मानित किया उससे बापू-बा प्रसंग याद आ गया। गांधी जी ने अपने आश्रम में पूज्य कस्तूरबा गांधी को स्वच्छता मंत्र देकर शौचालय साफ करवाये थे। डिंडोरी में जनपद पंचायत की अध्यक्षा ने बापू के उसी स्वच्छता मंत्र तथा प्रधानमंत्री के स्वच्छता अभियान से प्रेरणा लेकर प्रत्येक घर में शौचालय निर्माण सुनिश्चित करने के लिये विशेष अभियान संचालित किया। चौपालें लगाकर और निगरानी समितियां बनाकर खुले में शौच क्रिया बंद करवाने में सक्रिय जनसहयोग प्राप्त किया। उन्होंने न केवल अपने प्रभार के प्राकृतिक संसाधनों का युक्तियुक्त प्रबंध करके, स्वपोषित विकास सुनिश्चित किया बल्कि गांवों के सर्वतोमुखी विकास के लिये सक्रियवादी रास्ता अपनाया जिस प्रकार गांधी जी ने तकली और तालीय, चरखा और चेतना तथा गरीबी और ग्रामोद्योग को ग्राम स्वराज से जोड़ा था उसी प्रकार ठीक वैसे ही सर्वोदयी मॉडल पर मध्यप्रदेश की पंचायतें ग्रामोदय से भारतोदय को अमली जामा पहना रही हैं।

राष्ट्रीय स्तर पर पंचायत सशक्तीकरण एवं जवाबदेही पुरस्कार योजना वर्ष 2015-16 के लिये मध्यप्रदेश की दो जिला पंचायतों यथा इंदौर और देवास, दो जनपद पंचायतों यथा बैरसिया (जिला भोपाल) तथा डिंडोरी (जिला डिंडोरी) और एक दर्जन ग्राम पंचायतों को पुरस्कृत किया गया है। इनमें से छह पंचायतें होशंगाबाद जिले में (सांगाखेड़ा, सहेली, कोहनी, सेमरीहरचंद, परराँदेह और रंढाल), दो-दो क्रमशः देवास (नयापुरा और बचरवाल) और हरदा में (हरदा खुर्द और बारंगा) एवं एक-एक अनूपपुर (जैतहरी और सीहोर जिले (सीहोर)) में हैं। होशंगाबाद जिले में ही किशनपुर ग्राम पंचायत को राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय गौरव ग्रामसभा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

पंचायतराज दिवस के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा था कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी सेवाएं और सुविधायें नगरों के समान ही होना चाहिये। उन्होंने पंचायतों को बजट से परे सोचने के लिये प्रोत्साहित

करते हुए कहा कि जन सुविधाओं पर ध्यान केन्द्रित करें। मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान ने स्वयं गांवों में जाकर ग्रामीणों से विचार-विमर्श करने तथा उन्हें ही अपनी बात कहकर गांव की समस्या बताने को प्रोत्साहित करने हेतु ग्राम संसदों का अनूठा आयोजन किया। कुछ ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री के प्रति व्यवहारिक आभार प्रदर्शन किया। उदाहरणार्थ हरदा जिले में मूंग की फसल के लिये सिंचाई उपलब्ध कराने हेतु ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री का सम्मान मूंग से तौलकर किया। इस मूंग को आंगनवाड़ी केन्द्रों में पोषण आहार के रूप में उपयोग किया जायेगा।

ग्राम पंचायतों में गरीबी रेखा के नीचे वाले व्यक्तियों को उनका हक दिलाने की चेतना बड़ी है। अब ग्राम सभा की बैठकों में बी.पी.एल. सूची पढ़कर सुनाई जायेगी और जो नाम छूट गये हैं उन्हें 31 मई तक जोड़ा जायेगा। ग्रामीणों को खुले में शौच से मुक्त कराने के लिये गांव-गांव में जो प्रयास किये जा रहे हैं उनमें रायसेन के खरबई जिले का मॉडल विशेष रूप से उल्लेखनीय है। यहां 21 युवकों ने संकल्प लिया था कि जब तक गांव का एक भी व्यक्ति खुले में शौच करेगा वे नंगे पांव ही रहेंगे और जूते नहीं पहनेंगे। जब गांव पूर्णतः स्वच्छ हो गया तो वहां कचरे से कंचन योजना का शुभारंभ किया गया।

ग्राम पंचायतों और ग्राम संसदों के माध्यम से ग्रामीण जनता की सर्वतोमुखी विकास में भागीदारी प्रजातंत्र का मूलाधार है। बहुत-सी योजनायें ऐसी हैं जिन्हें ग्रामीण बिना बाहरी सहायता के स्वयं ही कार्यान्वित कर सकते हैं। स्वच्छता, वृक्षारोपण, जल संचय आदि ऐसे ही प्रकल्प हैं। यदि गांवों में जलमल-निकास की बेहतर व्यवस्था हो जाये तो स्वच्छता अभियान स्वतः आगे बढ़ जायेगा। हर्ष का विषय है कि मध्यप्रदेश के ग्रामों में यह चेतना पहले से है। अब ग्रामोदय अभियान के तहत इसे और बल मिला है, दस हजार से अधिक ग्राम संसदें आयोजित की जा चुकी हैं। लगभग 12 हजार (स्वास्थ्य शिविर संगठित किये गये हैं। प्रकरणों का घटना स्थल पर ही निपटारा हो रहा है। नामान्तरण के 44732 प्रकरणों, सीमांकन के 3820 और बंटवारे के 6500 प्रकरणों का निपटारा हो गया है। यह उपलब्धियां तो 45 दिन के इस अभियान में मात्र एक पखवाड़े की हैं।

वास्तव में गांधीवादी प्रबंधन सिद्धांत जिन्हें ग्रामोदय में प्रेरक माना गया है, स्थानीय नवाचार पर बल देते हैं। गांधी जी कहते थे कि हर ग्रामवासी को किसी न किसी समाजोपयोगी उत्पादक गतिविधि में भाग लेना चाहिये। गांव को स्वच्छ रखना भी रचनात्मक गतिविधि है। शिक्षित वर्ग द्वारा शिक्षा-प्रसार भी उत्पादक गतिविधि है। नशामुक्ति उपयोगी पहल है। परिवार नियोजन खुशहाली का मूलमंत्र है। वृक्षारोपण और जल संचय से भूमि तथा जल संरक्षण होता है। उपज बढ़ जाती है। प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉ. रघुनाथ मशेलनकर ने इसे गांधीवादी इंजीनियरिंग कहा है जिससे न्यूनतम व्यय से अधिकतम लोगों को अधिकतम लाभ पहुंचाया जा सकता है। इन योजनाओं के लिये शासकीय स्वीकृति या बजट प्रावधानों की जरूरत नहीं होती। किसानों द्वारा फलदार वृक्ष लगाकर अपनी आय बढ़ाना एक प्रकार की आर्थिक क्रांति है। इसका मॉडल मुख्यमंत्री जी खुद अपने स्वयं के अनुभवों से प्रस्तुत करते रहते हैं। गांधी जी की ग्राम स्वराज अवधारणा की ऐसी अनेक चरित्रगत विशेषतायें हैं जिन्हें मध्यप्रदेश में ग्रामोदय अभियान का प्रस्थान बिन्दु माना गया है। गांधी जी ने राजनीतिक स्वाधीनता को सर्वोदय के माध्यम से पूर्ण स्वराज में बदला था।

पं. दीनदयाल उपाध्याय जी का एकात्म मानववाद भी यही सब तो बताता है। मध्यप्रदेश इसी रास्ते पर दृढ़ संकल्पित होकर अग्रसर है।

राष्ट्रीय स्तर पर पंचायत सशक्तीकरण एवं जवाबदेही पुरस्कार योजना वर्ष 2015-16 अंतर्गत पुरस्कार प्राप्त करने वाली जिला, जनपद व ग्राम पंचायतों की सूची

1.	जिला पंचायत देवास	
2.	जिला पंचायत इंदौर	
1.	जनपद पंचायत	बैरसिया, जिला भोपाल
2.	जनपद पंचायत	डिण्डोरी, जिला डिण्डोरी

क्र.	ग्राम पंचायत	जनपद पंचायत	जिला पंचायत
1.	सांगाखेड़ा	बाबई	होशंगाबाद
2.	सहेली	केसला	होशंगाबाद
3.	कोहनी	सोहागपुर	होशंगाबाद
4.	सेमरीहरचंद	सोहागपुर	होशंगाबाद
5.	परर्रादेह	होशंगाबाद	होशंगाबाद
6.	रंढाल	होशंगाबाद	होशंगाबाद
7.	नयापुरा	बागली	देवास
8.	बचखाल	खातेगांव	देवास
9.	हरदाखुर्द	हरदा	हरदा
10.	बारंगा	खिरकिया	हरदा
11.	छातापटपर	जैतहरी	अनूपपुर
12.	निपानिया कलां	सीहोर	सीहोर

राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार वर्ष 2015-16

क्र.	ग्राम पंचायत	जनपद पंचायत	जिला पंचायत
1.	किशनपुर	सोहागपुर	होशंगाबाद

● **घनश्याम सक्सेना**

ग्रामोदय से भारत उदय तक

लोकतंत्र का सच्चा स्वरूप पंचायतों के भीतर

शून्य से सृष्टि प्रकृति का एक शाश्वत सिद्धांत है। विज्ञान की भाषा में कहें तो यह एनर्जी के एक एटम में हुए विस्फोट से ही संसार विस्तारित हुआ है। इन दोनों बातों का मतलब एक है कि जो भी आज विराट है, विशाल है, व्यापक है उसकी बुनियाद अतिसूक्ष्म है। यदि बुनियाद मजबूत है तो ही भवन मजबूत होगा। सूक्ष्म का सशक्त होना ही विराट के दीर्घ जीवन का आधार है।

प्रकृति का यह सिद्धांत जीवन के प्रत्येक आयाम पर लागू होता है। नीतियां बनाने, निर्णयों को लागू करने में यदि इस आधारभूत सिद्धांत का ध्यान रखा जाये तो ही योजनाओं के परिणाम कल्याणकारी होंगे। भारत के लोकतंत्र में यदि हम आज कुछ व्यवहारिक विसंगतियां देख रहे हैं उसका कारण केवल यह है कि हमने आजादी के बाद 'सूक्ष्म पर ध्यान कम दिया और सारा चिंतन केवल' विराट पर हुआ, इसीलिए आज केवल 68 सालों में राष्ट्र जीवन पर संकट घिरने लगा है।

ग्रामोदय से भारत उदय अभियान

किसी भी देश की सूक्ष्म इकाई गांव है और सरकार की सूक्ष्म इकाई पंचायतें। यदि गांव समृद्ध हुए और पंचायतें सशक्त हुई तब राष्ट्र की समृद्धि को कोई रोक नहीं सकता। इस दिशा में पहली बार वर्तमान सरकार ने बाकायदा गांवों के सशक्तीकरण का अभियान चलाया और उसका नाम दिया "ग्रामोदय से भारत उदय"।

यदि हम देखें तो शहरों में विकास की तीव्रतम दौड़ तो दिखती है लेकिन नगरों के विकास की बुनियाद गांवों में है। शहरों की चमचमाती सड़कों की रेत और गिट्टी गांवों से आती है। पांच सितारा होटलों में बनने वाले व्यंजन के लिए अनाज, फल, सब्जी सब गांवों से आती है। यही नहीं गांवों के लोग ही अपनी सिंचाई की जरूरतों में कटौती करके नगरों में पीने के लिए पानी भेजते हैं। यदि हम इन तर्कों के भीतर न जाएं तब भी इतिहास का वह सत्य गवाह है कि जिन दिनों भारत सोने की चिड़िया माना जाता था उन दिनों भारत की अर्थव्यवस्था में 80 प्रतिशत से ज्यादा योगदान भारत की कृषि और शिल्प का था। आज हालांकि ग्राम आधारित अर्थव्यवस्था के आंकड़ों में परिवर्तन आया है और यह घटकर 25 प्रतिशत रह गई। तब भारत की गिनती दुनिया के गरीब देशों में होने लगी। इसका सीधा अर्थ है कि भारत के विकास में कोई ऐसा बिन्दु है जो छूट रहा है अथवा जिसकी अनदेखी की जा रही है। गांवों के विकास को प्राथमिकता देने का अर्थ या आशय यह कतई

14 अप्रैल को संविधान निर्माता डॉ. भीमराव अंबेडकर की जयंती थी। डॉ. अम्बेडकर ने भारत में सामाजिक समरसता का बड़ा अभियान छेड़ा और शस्त्रोक्त विधि से उन व्यक्तियों और विचारों की आलोचना की जो लोगों को बांटना चाहते थे। ग्रामोदय अभियान के विभिन्न बिन्दुओं में एक बिन्दु सामाजिक समरसता का भी है जबकि अन्य बिन्दुओं में स्वास्थ्य, स्वच्छता, जल संरक्षण जैसे विषय शामिल हैं।

नहीं है कि नगरों का विकास रोक दिया जाए। आज यदि भारत को दुनिया की दौड़ में आगे निकलना है तब नगरों का स्मार्ट बनना और बनाना तो जरूरी है लेकिन उसकी बुनियाद गांवों से होनी चाहिए। गांव सशक्त हो, संपन्न हो, समृद्ध हो तभी राष्ट्र समृद्ध होगा। जो देश अपना पेट भरने लायक अनाज पैदा न कर सके उसकी संपन्नता की कल्पना करना अनुचित होगा। खासतौर से तब जब टेक्नालॉजी में गला काट स्पर्धा चल रही हो।

आज भारत जैसे देश के लिए कम से कम दो तीन बातों को अभियान के रूप में हाथ में लेना होगा। एक सामाजिक समरसता और दूसरी गांवों को समृद्ध बनाना आपस के वैमनस्य के वातावरण में जीकर यदि कोई परिवार तरक्की नहीं कर पाता तब बैर-वैमनस्य के वातावरण के बीच कोई देश तरक्की कैसे करेगा। यदि हम अपने भोजन के लायक दाल का उत्पादन नहीं कर पाते, अपनी फसल का भंडारण नहीं कर पाते या किसान का मन गांव-खेती से उचट रहा है तब देश की समृद्धि की कल्पना की ही नहीं जा सकती। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी के इस अभियान में इन्हीं विसंगतियों को दूर करने का संदेश है। जिस अभियान की शुरुआत उन्होंने 14 अप्रैल को मध्यप्रदेश के महू से की थी उसका समापन उन्होंने झारखंड के जमशेदपुर में किया। भारत सरकार ने इस अभियान को दस दिनों तक चलाने की अपील की थी और राज्य सरकारों को यह अधिकार दिया था वे अपनी सुविधा के अनुसार तिथियों में परिवर्तन कर सकते हैं। हालांकि मध्यप्रदेश सरकार ने इसे बढ़ाकर डेढ़ माह कर दिया था पूरे देश में भले ही यह अभियान दस दिन चला लेकिन मध्यप्रदेश में यह डेढ़ माह चलेगा और समापन 30 मई को होगा।

राष्ट्रीय स्तर के अभियान के आरंभ एवं समापन होने की तिथियों का भी अपना महत्व है। 14 अप्रैल संविधान निर्माता डॉ. भीमराव अम्बेडकर की जयंती थी। डॉ. अम्बेडकर ने भारत में सामाजिक समरसता का बड़ा अभियान छेड़ा और शस्त्रोक्त विधि से उन व्यक्तियों और विचारों की आलोचना की जो व्यक्तियों को बांटना चाहते थे। ग्रामोदय के अभियान के विभिन्न बिन्दुओं में एक बिन्दु सामाजिक समरसता का भी है जबकि अन्य बिन्दुओं में स्वास्थ्य, स्वच्छता, जल संरक्षण जैसे विषय शामिल हैं। दूसरी ओर समापन के लिए केंद्र द्वारा निर्धारित 24 अप्रैल की तिथि राष्ट्रीय पंचायतीराज दिवस के रूप में जानी जाती है। इस तिथि के निर्धारण के पीछे यह संदेश देना भी है कि यदि गांवों का विकास जरूरी है, उनकी समृद्धि जरूरी है तो गांवों पर शासन करने की अथवा गांवों की व्यवस्था देखने वाली इकाई पंचायतों का आत्मनिर्भर होना भी जरूरी है। यह बात केवल स्थानीय पंचायत ही समझती है कि उस गांव की विशेषता क्या है, उसकी मानसिकता क्या है, जरूरत क्या और समस्या क्या है। जब तक देश के विकास में आमजन भागीदार नहीं होगा तब तक समृद्ध नहीं होगा। यही बुनियादी भाव इस ग्रामोदय से राष्ट्र उदय अभियान का मूल है।

मध्यप्रदेश में इस अभियान ने प्रशासन और गांवों के बीच के रिश्तों में गहरी सघनता ला दी है। प्रशासन के प्रमुख सचिव से लेकर न्यूनतम इकाई पटवारी तक सभी सतत दौरे कर रहे हैं। सभाएं चल रही हैं, सम्मेलन हो रहे हैं। हालांकि यह मौसम प्रकृति की प्रतिकूलताओं से भरा रहा। कभी 45 और 46 डिग्री के तापमान की तेज तपन तो कभी तेज आंधी-पानी की प्रचंडता के बावजूद न तो

प्रशासनिक अमले की गति में अंतर आया और न जनप्रतिनिधियों के उत्साह में। मंत्रियों, विधायकों और अन्य जनप्रतिनिधियों ने विशेषकर स्वच्छता और समरसता अभियान में स्वयं सभाएं कीं तथा ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए जिससे लोगों को प्रेरणा मिले, उत्साह आए प्रशासनिक अमले और जनप्रतिनिधि दोनों ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी के उन शब्दों को अपनी कार्यशैली का मूलमंत्र माना जो उन्होंने महू और जमशेदपुर में कहे थे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने मध्यप्रदेश में अभियान के शुभारंभ में जहां समरसता पर बहुत जोर दिया था वहीं जमशेदपुर में सफाई और स्वास्थ्य पर जोर दिया। उन्होंने ग्राम पंचायतों से अपील की कि वे संसाधनों का पूरा लाभ उठाएं। उन्होंने स्पष्ट किया कि पंचायत दिवस के मौके पर देश की प्रगति गांवों के विकास पर काफी निर्भर करती है। उन्होंने साथ ही दूरदराज के इलाकों में सभी आधुनिक सुविधाएं पहुंचाकर शहरों और ग्रामीण इलाकों के बीच की दूरी पाटने की जरूरत पर भी जोर दिया। किसानों, महिलाओं और शिशुओं की देखभाल के साथ प्रगति पर जोर देते हुए कहा कि वह अपने पांच साल के कार्यकाल के बाद एक विरासत छोड़ना चाहते हैं जिसकी आने वाले सालों में असाधारण उपलब्धि के लिहाज से बात की जाएगी। मोदी ने कहा, हमें पंचायतों को मजबूत करने की जरूरत है। उन्होंने ग्राम पंचायतों और केंद्र सरकार के बीच सहयोग की जरूरत को रेखांकित करते हुए कहा, हमें सपनों को पूरा करने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर काम करना होगा।

प्रधानमंत्री ने गांवों की प्रगति पर जोर देते हुए ग्राम प्रधानों को विकास गतिविधियों में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए कहा। बुनियादी ढांचे के विकास, खुले में शोच का अंत, उचित स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने और बच्चे स्कूल न छोड़ें उसके लिए बेहतर शिक्षा का प्रावधान करने में अग्रणी भूमिका निभाने को कहा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश की महिला पंचायत प्रतिनिधियों से महिलाओं को खुले में शौच नहीं जाना पड़े इसके लिये कार्य करने का अनुरोध करते हुए कहा कि वर्ष 2019 तथा महात्मा गांधी के सपनों का गांव बनाने का संकल्प लेना होगा। श्री मोदी ने कहा कि वर्ष 2019 में महात्मा गांधी की 150वीं वर्षगांठ है और उस समय तक ग्रामोदय का बीड़ा उठाकर इसे अभियान के रूप में चलाते रहें तो गांधीजी के सपनों का गांव बनाने में सफल रहेंगे।

• **रमेश शर्मा**

सीख समझाईश और समस्या निदान

गाँवों को विकास की मुख्यधारा में जोड़ने और वहाँ आधारभूत विकास करने के लिए सरकार द्वारा ग्रामोदय से भारत उदय अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत सभी ग्राम पंचायतों में ग्राम सभा का आयोजन किया गया। जिसमें ग्राम पंचायत के सदस्य, ग्रामीणों के साथ-साथ राज्य स्तरीय तथा जिला स्तरीय अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी भाग लिया। इसमें ग्रामीणों की समस्याएँ सुनीं और सुझाव मांगे। इसी कड़ी में पंचायतराज संचालनालय के संचालक सह आयुक्त श्री संतोष मिश्र 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस पर भोपाल जिले के फंदा जनपद की ग्राम पंचायत बरखेड़ी अब्दुल्ला का निरीक्षण कर ग्रामीणों से रूबरू हुए। ग्राम पंचायत द्वारा आयोजित बैठक में श्री मिश्र ने ग्रामवासियों से पंचायतराज संचालनालय द्वारा संचालित योजनाओं और ग्राम उदय से भारत उदय कार्यक्रम के तहत हो रहे कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान ग्राम पंचायत बरखेड़ी अब्दुल्ला के सरपंच ने बताया कि गाँव में विद्युत आपूर्ति अनियमित हो रही है जिससे यहाँ पेयजल आपूर्ति में काफी दिक्कतें आ रही हैं। उन्होंने बताया कि कई किसानों ने खेतों में सिंचाई के लिए ट्यूबवेल लगा रखे हैं ऐसे में बिजली कटौती से उनके पास सिंचाई व्यवस्था होने के बावजूद वे सिंचाई नहीं कर पा रहे जिससे फसल का भारी नुकसान हो रहा है। समस्या के त्वरित समाधान के लिए आयुक्त पंचायत राज ने मध्यप्रदेश विद्युत मंडल के कार्यपालन यंत्री को तुरंत कार्यवाही करने के निर्देश दिए। चर्चा के दौरान ग्रामीणजनों ने गाँव में पेयजल समस्या से अधिकारियों को अवगत कराया। उन्होंने बताया कि गाँव में पेयजल की गंभीर समस्या है। भीषण गर्मी के कारण अधिकांश हैण्डपंपों में जलस्तर बहुत नीचे चले जाने से पानी नहीं आ रहा है। पानी की समस्या का असर कृषि पर भी पड़ रहा है। श्री संतोष मिश्र ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यपालन यंत्री को ग्राम बरखेड़ी अब्दुल्ला में पेयजल समस्या के निदान के लिए निर्देश दिया और कहा कि जिन हैण्डपंपों का जल स्तर नीचे चला गया है उनमें टाईजर पाईप लगवाएं ताकि जिससे पानी मिल सके। यदि इस प्रक्रिया से भी पानी न मिले तो वहाँ सिंगल फेस मोटर पम्प लगा कर पेयजल आपूर्ति की जाए। उन्होंने गाँव में समस्त जल स्रोतों, कुओं, तालाबों के गहरीकरण करने के लिए भी निर्देशित किया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणजनों को भी जल का महत्व समझाया और जल संरक्षण और जल संवर्धन के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि यदि वर्षा जल का समुचित संग्रहण किया जाए तो सिंचाई के लिए भरपूर पानी तो मिलेगा ही साथ ही सालभर भूजल स्तर भी बना रहेगा जिससे हैण्डपंपों में पर्याप्त पानी रहेगा।

• मोहन सिंह पाल

गाँव की योजना अब गाँव में बनेगी

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने 28 अप्रैल को सागर जिले के ग्राम रानीपुरा में आयोजित 7 ग्रामों की ग्राम संसद को संबोधित करते हुए कहा है कि गाँव के सर्वांगीण विकास के लिये प्रदेश के प्रत्येक गाँव की योजना अब गाँव में बनेगी। उन्होंने कहा कि किसानों की माली हालत सुधारने के लिये राज्य सरकार ने कृषि विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। उन्होंने सतगढ़ सिंचाई परियोजना के लिये 436 करोड़ रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति को भी मंजूरी दी।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने 3 करोड़ 79 लाख रुपये के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि-पूजन भी किया। इस मौके पर नरियावली विधायक सर्वश्री प्रदीप लारिया, शैलेन्द्र जैन, हरवंश सिंह राठौर, श्रीमती पारुल साहू और सागर महापौर श्री अभय दरे भी मौजूद थे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रत्येक ग्रामवासी ग्रामसभा की बैठक में मौजूद रहकर विकास का प्लान तैयार करवाये। उन्होंने कहा कि ग्रामसभा में बीपीएल सूची को पढ़कर सुनाया जायेगा। जो पात्र व्यक्ति इसमें जुड़ने से छूट गये हैं, उनके नाम 31 मई तक जोड़े जायें। मुख्यमंत्री ने महिलाओं से कहा कि प्रधानमंत्री ने निर्धन परिवारों के लिये एलपीजी कनेक्शन निःशुल्क देने की योजना बनायी है। प्रदेश में इसका जल्द ही क्रियान्वयन शुरू किया जायेगा।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने फसल बीमा योजना की चर्चा करते हुए कहा कि अब किसानों के फसल नुकसान पर कोई दिक्कत नहीं आयेगी। उन्होंने कहा कि फसल बीमा योजना को सरल बनाया गया है। उन्होंने किसानों को परम्परागत खेती के साथ उद्यानिकी फसल को अपनाने की समझाईश भी दी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने ग्राम रानीपुरा में 23 एकड़ में खेती के मॉडल फार्म हाउस का शुभारंभ भी किया।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने ग्राम संसद में मौजूद ग्रामीणों, विशेषकर महिलाओं को ईमानदारी से गाँव के विकास में सहभागी बनाने का संकल्प दिलवाया।

उन्होंने कहा कि राज्य में इस वर्ष से विद्यार्थियों को सायकल के लिये नगद राशि की बजाय सायकल उपलब्ध करवायी जायेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के निःसंतान दम्पतियों का उपचार राज्य सरकार करवायेगी। ऐसी 3000 बहनों को चिन्हित कर लिया गया है।

कार्यक्रम को पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि गाँव के विकास के लिये धन की कमी को आड़े नहीं आने दिया जायेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल संकट के लिये ग्राम पंचायत को पर्याप्त राशि दी जायेगी।

कलेक्टर श्री विकास नरवाल ने बताया कि 'ग्रामोदय से भारत उदय' अभियान में सागर जिले में अब तक 1619 आयोजन हुए हैं।

किसानों की स्थिति में सुधार और उन्हें बेहतर समाधान देना सर्वोच्च प्राथमिकता

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने 25 अप्रैल को देवास जिले के ग्राम टिमरिया गोगा में ग्राम संसद में कहा कि किसानों की स्थिति में सुधार लाना और उन्हें खेती-किसानी के लिये बेहतर सुविधाएँ उपलब्ध करवाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बाद अब किसानों को फसल नुकसानी पर आर्थिक रूप से कोई परेशानी नहीं होगी। उन्होंने किसानों से कहा कि वे परम्परागत खेती को छोड़कर कृषि की नई तकनीक और कृषि यंत्रों का उपयोग करें, खेती का पेटर्न बदलें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ड्रिप स्प्रिंकलर पद्धति से सिंचाई करें। इससे हम नहरों और अन्य सिंचाई साधनों से दो से तीन गुना क्षेत्र में अधिक सिंचाई कर पायेंगे। उन्होंने गाँव में छोटे-छोटे उद्योग लगाने का भी ग्रामीणों को सुझाव दिया और कहा कि वे युवाओं को मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना का लाभ उठाने के लिये प्रेरित करें। श्री चौहान ने बताया कि स्व-सहायता समूहों को सशक्त बनाने के साथ ही फूड प्रोसेसिंग से जुड़ी कम्पनियों को प्रदेश में निवेश के लिये आमंत्रित किया गया है।

वर्ष 2022 तक प्रदेश के हर आवासहीन परिवार को मकान बनाकर दिया जायेगा। मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों से आग्रह किया कि वे अपने घरों में शौचालय बनवायें और गाँव को खुले में शौच से मुक्त करें। नशामुक्ति अभियान चलायें, गाँव को नशामुक्त करें। उन्होंने ग्रामीणों को अपने-अपने गाँव को आदर्श बनाने का संकल्प भी दिलवाया। मुख्यमंत्री ने गाँव की सर्वाधिक शिक्षित बालिका रीना, सर्वाधिक वृक्षारोपण के लिये श्री बद्रीलाल, स्वच्छ घर के लिये किशोर, वार्ड की स्वच्छ गली के लिये श्रीमती पुष्पाबाई और आकर्षक रंगोली बनाने के लिये पूजा डाबर को सम्मानित किया।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने ग्राम संसद महोली में लिया हिस्सा

अशोकनगर जिले में 09 मई को पंचायत एवं ग्रामीण विकास, सामाजिक न्याय मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने चंदेरी विकासखंड के ग्राम महोली में ग्राम उदय से भारत उदय अभियान अन्तर्गत ग्राम संसद की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि ग्राम में हितग्राहीमूलक योजनाओं में तथा ग्राम के विकास में प्रगति कैसे आये इस संबंध में हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने विचार किया कि हमारी संसद कहा से प्रारंभ हो? इस विषय में उन्होंने तय किया कि हमारी संसद ग्राम से प्रारंभ हो और ग्राम में ही ग्राम के विकास की योजना ग्राम के सभी लोग एक जगह बैठकर बनाएं, कृषि विकास की योजना बनाएं, ग्राम के लोग ही तय करें कि हमारे ग्राम में कौन गरीब है और कौन किस योजना के लिए पात्र है, ऐसी इच्छा से इस कार्यक्रम को बनाया गया है। श्री भार्गव ने ग्राम ससंद को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा में लोगों को अब किसी प्रकार के नुकसान होने पर उनके नुकसान की भरपाई हो सकेगी। 25 प्रतिशत नुकसान का मुआवजा तत्काल मिलेगा। पहले बैंक किसानों को 25 प्रतिशत ब्याज पर ऋण देती थी, जिसे हमने धीरे-धीरे घटाते हुए 0 प्रतिशत कर दिया है।

ग्राम संसद की बैठक में माननीय मंत्री जी ने संबोधन में कहा कि ग्राम के लोग बैठक कर सूची बना लें, तय कर लें कि हमारे ग्राम का सबसे गरीब व्यक्ति कौन है, उसके पास मकान है या नहीं, उसके पास साइकिल है या नहीं।

हम तय कर लें कि उस गरीब व्यक्ति को कुटीर उद्योग मिल जाए। यदि हम ऐसा कर पाये तो हमारे दीनदयाल जी का सपना पूर्ण हो जाएगा। कोई भी पात्र व्यक्ति योजना में नहीं छूटे हमें इस बात को तय करना है। इस ग्राम संसद में और गरीब का नाम जुड़वाने के भागीदार बनें। ग्राम उदय से भारत उदय अभियान ऐसा अभियान है, जिसमें ग्राम के लोग स्वयं बैठकर अपने ग्राम के विकास की योजना बनाएंगे और योजना अनुसार उनके ग्राम के विकास कार्य होंगे।

टिमरनी विकासखण्ड खुले में शौच से मुक्त

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने 27 अप्रैल को हरदा जिले के टिमरनी विकासखण्ड के ग्राम खिड़कीवाला में ग्रामोदय से भारत उदय अभियान में हुई ग्राम संसद को संबोधित करते हुए कहा कि हर गाँव आगे बढ़ेगा, तभी मध्यप्रदेश का विकास होगा। इस कार्य में "ग्रामोदय से भारत उदय" अभियान सार्थक सिद्ध होगा। अभियान में प्रत्येक गाँव को अपने विकास की योजना स्वयं तय करनी है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने टिमरनी विकासखण्ड को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया। उन्होंने इस कार्य में सहयोग देने वाले जन-प्रतिनिधियों और कर्मचारियों का सम्मान भी किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अभियान का मुख्य उद्देश्य गाँव में उपलब्ध संसाधनों से गाँव के विकास को गति देना, कृषि के विकास की रणनीति तैयार करना, फसल पद्धति में बदलाव लाना, नदियों को पुनर्जीवित करना और पात्र हितग्राहियों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलवाना है। उन्होंने कहा कि हरदा को ग्रामीण आजीविका मिशन में शामिल किया गया है। इससे ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को रोजगार के अधिक अवसर मिलेंगे। उन्होंने वर्ष 2022 तक सभी को मकान उपलब्ध करवाने के संकल्प को दोहराया। मुख्यमंत्री ने गाँव की सबसे ज्यादा पढ़ी-लिखी बेटी सुश्री सीमा घुड़लाल डोंगरे और बहू श्रीमती शीतला मयंक तिवारी को भी सम्मानित किया। उन्होंने जिले के 12 अनुसूचित जाति-जनजाति छात्रावासों को आईएसओ प्रमाण-पत्र वितरित किये। कुछ किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड भी दिये। इस अवसर पर मुख्यमंत्री का हरदा जिले में मूँग की फसल को सिंचाई के लिये नहर का पानी उपलब्ध करवाने पर मूँग से तुलादान किया गया। इस मूँग का आँगनवाड़ी केन्द्रों में पोषण-आहार के रूप में उपयोग किया जायेगा। कार्यक्रम में लोक निर्माण एवं जिले के प्रभारी मंत्री श्री सरताज सिंह, विधायक श्री संजय शाह और श्री आर.के. दोगने, पूर्व मंत्री श्री कमल पटेल तथा अन्य जन-प्रतिनिधि उपस्थित थे।

ग्राम संसद : मुख्यमंत्री की उपस्थिति में ग्राम संसद में खिड़कीवाला के सरपंच, सचिव और पटवारी ने ग्राम विकास का प्रतिवेदन पढ़ा। उन्होंने ग्रामोदय से भारत उदय अभियान के कार्यों, लाभान्वित हितग्राहियों तथा शत-प्रतिशत नामांतरण, बँटवारा के संबंध में जानकारी सार्वजनिक रूप से दी। कलेक्टर श्री श्रीकांत भनोट ने अभियान में किये गये कार्यों का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

ग्रामीणों के सहयोग से बनेगी ग्राम विकास की योजना

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने 28 अप्रैल को टीकमगढ़ के पुछी करगुवाँ में ग्राम संसद में कहा कि अब प्रदेश में ग्राम विकास की योजना ग्रामीणों के सहयोग से बनेगी। उन्होंने कहा कि ग्रामवासी अब अपनी प्राथमिकताएँ खुद तय करेंगे। इस मौके पर सरपंच श्री अलख प्रसाद वाल्मीक ने ग्राम विकास योजना का वाचन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि 'ग्रामोदय से भारत उदय' अभियान के दौरान महिलाओं का स्वास्थ्य परीक्षण किया जायेगा। उन्होंने कहा कि ऐसी महिलाओं का इलाज राज्य शासन करवायेगा, जो निःसंतान हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्राम में मौजूद निःशक्तजन को पात्रतानुसार सहायता दी जायेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बेतवा और जामनी नदी को जोड़कर पेयजल का स्थायी समाधान किया जायेगा। पुछी करगुवाँ में नल-जल योजना प्रारंभ कर घर-घर में नल से पानी पहुँचाये जाने की व्यवस्था की जायेगी।

उन्होंने कहा कि बाणसुजारा और अन्य सिंचाई परियोजनाओं को केन-बेतवा लिंक परियोजना से जोड़कर सिंचाई योजना का विस्तार किया जायेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि चंदेलकालीन तालाबों की समृद्धशाली परम्परा रही है। इन तालाबों को संरक्षित किया जायेगा। मुख्यमंत्री ने लाड़ली लक्ष्मी योजना के प्रमाण-पत्र और मृदा स्वास्थ्य-कार्ड भी हितग्राहियों को वितरित किये।

राष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल हुईं प्रदेश की

एक सौ सात आदिवासी महिला सरपंच

भारत सरकार के पंचायतराज मंत्रालय के तत्वावधान में पांचवीं अनुसूची के क्षेत्रों की आदिवासी महिला सरपंचों के राष्ट्रीय सम्मेलन में मध्यप्रदेश के 10 जिलों की 107 ग्राम पंचायतों की महिला सरपंचों ने भागीदारी की। राष्ट्रीय सम्मेलन 19 अप्रैल 2016 को आंध्रप्रदेश के विजयवाड़ा में आयोजित किया गया था। जिसका विषय था "पांचवीं अनुसूची के क्षेत्रों के विकास में महिला सरपंचों की भूमिका"। इस सम्मेलन में भारत सरकार के ग्रामीण विकास पंचायतीराज एवं पेयजल और स्वच्छता मंत्री चौधरी वीरेन्द्र सिंह, आंध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री चन्द्रबाबू नायडू, आदिवासी मामलों के मंत्री श्री जोएल ओराम, भारत सरकार के पंचायतराज विभाग के राज्यमंत्री श्री निहालचंद, ग्रामीण विकास मंत्री श्री सुदर्शन भगत, पेयजल और स्वच्छता मंत्री श्री रामकृपाल यादव सहित आंध्रप्रदेश राज्य के विभिन्न विभाग के मंत्री एवं अधिकारीगण मौजूद रहे।

इस सम्मेलन में मध्यप्रदेश की 107 महिला सरपंचों सहित प्रदेश के विभिन्न राज्यों के 674 आदिवासी महिला सरपंचों एवं 200 से अधिक अधिकारीगणों ने भागीदारी की। इस सम्मेलन में विभिन्न प्रांतों की ग्राम पंचायतों से आयीं आदिवासी महिला सरपंचों ने अपने अनुभव साझा किये। कार्यक्रम के दौरान 'पेसा' अंतर्गत ग्राम पंचायत विकास योजना की तैयारी, पेसा का क्रियान्वयन, महिलाओं से संबंधित मुद्दे आदि पर भी विस्तार से चर्चा की गई।

इस सम्मेलन में भागीदारी के लिये मध्यप्रदेश के 10 जिलों की 107 आदिवासी महिला सरपंचों ने भाग लिया तथा मध्यप्रदेश में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के सफल क्रियान्वयन से मिले परिणामों के बारे में अपने विचार रखे। साथ ही इन महिला सरपंचों द्वारा अपनी-अपनी ग्राम पंचायतों में किये श्रेष्ठ कार्यों एवं उपलब्धियों के बारे में भी बताया गया।

ग्राम उदय से भारत उदय अभियान

किशोरी बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए उपयोगी

छिंदवाड़ा जिले में ग्राम उदय से भारत उदय अभियान के अंतर्गत जिले में किशारी बालिकाओं एवं महिलाओं के स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के लिए विशेष कार्य किया जा रहा है। प्रशासन द्वारा इस दिशा में कार्य करते हुए उन्हें निःशुल्क सेनेटरी नेपकिन वितरित किए जा रहे हैं। इस हेतु जिले में अनेक स्थानों पर उदिता कार्नर स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा अति कम वजन वाले बच्चों को स्वस्थ बनाने के उद्देश्य से उन्हें प्रतिष्ठित व्यक्तियों को गोद देने का कार्य भी किया जा रहा है। इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना अन्तर्गत गर्भवती महिलाओं को भी लाभांवित किया जा रहा है।

ग्रामीण किशोरी बालिकाओं को जानकारी के अभाव में माहवारी के दौरान स्वास्थ्य एवं स्वच्छता संबंधी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इन परेशानियों के कारण स्कूल एवं महाविद्यालयों में किशोरियों की उपस्थिति कम हो जाती है एवं वे खेलकूद गतिविधियों में भाग नहीं ले पातीं। इन परेशानियों से निजात दिलाने के लिए उनके स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के लिए कार्य किया गया। प्रोजेक्ट उदिता कार्यक्रम के तहत आंगनवाड़ी केन्द्र के अन्तर्गत आने वाली किशोरी बालिकाओं को स्वास्थ्य एवं स्वच्छता संबंधी जानकारी प्रदान की गई एवं माहवारी स्वच्छता के लिये सेनेटरी नेपकिन उपलब्ध कराए जाकर उनके उपयोग तथा सुरक्षित विनिष्टिकरण के बारे में विस्तार से बताया गया।

ग्राम उदय से भारत उदय अभियान के पूर्व जिले की कुल 3001 आंगनवाड़ी केन्द्रों में 2025 उदिता कार्नर स्थापित किये जा चुके थे। अभियान के दौरान इस कार्य को और प्राथमिकता से करते हुए 580 अन्य आंगनवाड़ी केन्द्रों में उदिता कार्नर स्थापित किये गये एवं ग्राम उदय से भारत उदय अभियान के दौरान कुल 3421 सेनेटरी नेपकिन का प्रदाय किशोरी बालिकाओं को किया गया।

आदिम जाति सेवक संघ सौंसर संस्था के अल्पावास गृह द्वारा सेनेटरी नेपकिन का निर्माण कराया गया जो किशोरी बालिका एवं महिलाओं को आंगनवाड़ी केन्द्र में उदिता कार्नर के माध्यम से वितरण किया जा रहा है। समाजसेवी संस्था लायनेंस क्लब, जैन समाज, परासिया से सहयोग प्राप्त कर निशुल्क नेपकिन वितरण किया जा रहा है।

स्नेह सरोकार योजना के तहत अति कम वजन के बच्चों को जनप्रतिनिधि, उद्योगपतियों, व्यवसायियों, टीचर, प्रोफेसर, स्वयंसेवी संस्थाओं, समाज सेवी, एवं प्रतिष्ठित व्यक्तियों को गोद दिलाया गया। उक्त गोद लेने वाले व्यक्तियों द्वारा उक्त अति कम वजन के बच्चे की सतत् निगरानी की जा रही है। जिससे बच्चे के वजन एवं स्वास्थ्य में सुधार लाने का प्रयास किया जा रहा है। ग्राम उदय से भारत उदय अभियान के पूर्व जिले के 2456 अतिकम वजन के बच्चों को गोद दिलाया गया। अभियान के दौरान 123 बच्चों को जनप्रतिनिधियों को गोद दिलाया गया।

इसी तरह इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना अन्तर्गत गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था के छटवें माह से नौवें माह के दौरान अनुदान की प्रथम किश्त राशि रुपये 3000/- एवं प्रसव पश्चात् 6 माह तक धात्री माता को अनुदान की द्वितीय किश्त राशि रुपये 3000/- का भुगतान हितग्राही महिला के बैंक खाते में सीधे किया जाता है। उक्त योजना सशर्त लाभ स्कीम है। जिसमें महिला का पंजीयन निकटस्थ आंगनवाड़ी केन्द्र में होना आवश्यक है।

गर्भावस्था के दौरान एवं पश्चात् सभी प्रकार के टीके, आयरन की गोलियों का सेवन कराया जा रहा है। उक्त योजना दम्पति के प्रथम दो प्रसव के दौरान ही प्रदान की जाती है। ग्राम उदय से भारत उदय अभियान के दौरान 351 महिलाओं के आवेदन पत्र प्राप्त किया गया एवं उन्हें योजना का लाभ दिलाये जाने की कार्यवाही की गई है।

● **मनोज बारस्कर**

ग्रामीणों ने खुद तय किया अपना विकास

सीधी जिले में ग्राम उदय से भारत उदय अभियान से जुड़कर ग्रामीणजन सहभागिता के साथ अपने गांव के विकास की इबारत लिख रहे हैं। कहना न होगा कि आजादी के 68 वर्षों बाद ग्रामीणों को ग्राम संसद के माध्यम से खुद के विकास के कार्यों को चुनने का अधिकार ग्राम उदय से भारत उदय अभियान से मिला है।

मध्यप्रदेश का दूरस्थ जिला सीधी की ग्राम पंचायतों में जनपदवार क्लस्टरवार ग्राम संसदों का सुनिश्चित आयोजन कराये जाने के लिए नोडल तथा संकुल अधिकारी के साथ प्रभारी अधिकारी भी नियुक्त किये गए हैं। कलेक्टर श्री विशेष गढ़पाले के कुशल निर्देशन में ग्रामसभाओं एवं ग्राम संसदों का आयोजन तथा पांच वर्षों की विकास योजना का निर्माण जारी है। प्रदेश स्तर से जिले की निगरानी करने आए उच्च शिक्षा आयुक्त श्री उमाशंकर उमराव ने ग्राम संसदों का अवलोकन कर ग्रामीणों द्वारा अपने विकास के लिए बनायी जा रही कार्ययोजना में भागीदारी निभाई। ग्राम संसदों में अधिकारी और कर्मचारी सभी कार्ययोजना निर्माण में अपेक्षित निगरानी तथा सहयोग प्रदान किया। ग्राम संसदों में गरीबी रेखा सूची का वाचन कर अपात्रों के नाम हटाये जाने की कार्यवाही भी की जा रही है। सम्पूर्ण अभियान में माननीय जनप्रतिनिधियों का सराहनीय सहयोग प्राप्त हो रहा है। उल्लेखनीय है कि ग्राम उदय से भारत उदय अभियान के लिए प्राथमिक रूप से 10 अप्रैल को समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों को कठौतहा में प्रशिक्षित कर आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराये गए। व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु जिले में स्वच्छ भारत अभियान के तहत खुले में शौच मुक्त हेतु मिशन 90 में लगाये गए अधिकारी कर्मचारियों द्वारा ग्रामीणों से सीधा संवाद कर ग्राम उदय से भारत उदय की ग्रामसभा एवं ग्राम संसदों के बारे में जानकारी दी गई। ग्राम पंचायत स्तर पर मुनादी कर ग्रामीणों को अवगत कराया गया। जिला स्तर से नियमित रूप से समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी गई। जनपदवार बनाये गए व्हाट्सअप ग्रुप के माध्यम से लगातार निगरानी की जा रही है।

● शिवप्रसाद सोनी

आपसी तालमेल से दूर हुई पेयजल समस्या

खण्डवा जनपद की ग्राम पंचायत बड़गांवमाली में गर्मी का मौसम आते ही कई घरों में पेयजल संकट उत्पन्न हो गया था, जैसे-जैसे गर्मी बढ़ रही थी गांव के पेयजल स्रोत सूख रहे थे, हालत यह थी कि गांव के कुछ घरों को छोड़ कर बाकी सभी घरों के लोग पीने के पानी के लिये पास के गांव से पानी लाने को मजबूर हो गये थे। ऐसे भीषण जल संकट के दौर में ग्राम उदय से भारत उदय अभियान अंतर्गत 25 से 27 अप्रैल तक ग्राम पंचायत बड़गांवमाली में ग्राम संसद का आयोजन हुआ। प्रथम दिवस एवं द्वितीय दिवस की ग्राम संसद के दौरान ग्रामीणों द्वारा पंचायत के समक्ष पेयजल समस्या का मुद्दा मुख्य रूप से रखा तृतीय दिवस की ग्राम संसद के दौरान स्थानीय विधायक एवं सीईओ जिला पंचायत द्वारा ग्राम संसद में सहभागिता की गयी। विधायक श्री देवेन्द्र वर्मा एवं सीईओ जिला पंचायत श्रीमती सुचिस्मिता सक्सेना द्वारा ग्रामीणों को समझाईश दी गयी कि नवीन पेयजल स्रोत को बनाने में कुछ समय लग जायेगा इतने समय तक ग्रामीणों की प्यास बुझाने के लिये गांव के लोगों को ही सहयोग देना होगा। जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों की समझाईश के चलते 02 ग्रामीणों श्री रघुपती पाटीदार व श्रीकृष्ण पाटीदार द्वारा स्वयं के पेयजल स्रोतों से ग्रामीणों को पेयजल दिये जाने पर सहमती दी गई। इस तरह तीन दिवसीय ग्राम संसद ने सभी ग्रामीणों के आपसी मनमुटाव भुला दिये एवं गांव के लोगों के द्वारा ही पेयजल संकट का समाधान कर दिया गया।

मलगांव की ग्राम संसद में ग्रामीणों ने नौ कुपोषित बच्चों को लिया गोद

ग्राम का समग्र विकास केवल निर्माण कार्यों से संभव नहीं है वहां के ग्रामीणों के व्यवहरिक जीवन में परिवर्तन भी ग्राम के विकास में अत्यावश्यक है। ग्रामोदय से भारत उदय अभियान अंतर्गत होने वाली ग्राम संसद ग्रामीणों के व्यवहारिक जीवन में भी परिवर्तन ला रही है। इसके खण्डवा जिले में कई उदाहरण सामने आ रहे हैं खालवा जनपद की ग्राम पंचायत मलगांव के नागरिकों ने भी ग्राम संसद के दौरान ऐसा ही उदाहरण प्रस्तुत किया। मलगांव ग्राम पंचायत में आदिवासी परिवार निवास करते हैं जो मेहनत मजदूरी करके जीवन यापन करते हैं जिस दिन यह परिवार काम पर नहीं जाते उनके भोजन की व्यवस्था नहीं हो पाती है। यही कारण है कि यह परिवार उनके बच्चों पर विशेष ध्यान नहीं दे पाते और यहां के बच्चे कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। मलगांव की ग्राम संसद के दौरान भी कुपोषण की समस्या पर चर्चा की गयी ग्रामीणों के सामने 9 ऐसे बच्चे आये जो कुपोषण से पीड़ित थे इन बच्चों को विशेष देखभाल की जरूरत थी परंतु परिवार के पास समय अभाव था ऐसे में इन परिवारों की आर्थिक और माली हालत देखते हुए गांव के सरपंच, उपसरपंच, रोजगार सहायक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता और 2 आम नागरिकों द्वारा इन 9 बच्चों को गोद लेने का संकल्प ग्राम संसद के दौरान लिया। जिन लोगों ने बच्चों को गोद लिया है वह यह सुनिश्चित करेंगे कि यह बच्चे नियमित रूप से आंगनवाड़ी में जायें, इन्हें आंगनवाड़ी में पोषण आहार समय पर उपलब्ध हो, इसके साथ-साथ इन लोगों द्वारा प्रतिदिन इन बच्चों के घर जाकर बच्चों की स्थिति देखी जायेगी एवं आवश्यकता होने पर स्वयं की तरफ से इन्हें पोषण आहार भी उपलब्ध कराया जायेगा।

मलगांव की ग्राम संसद के दौरान नशामुक्ति के विषय में भी चर्चा की गयी गांव के 8 युवक जो शराब की लत के आदि हो चुके थे उन्हें समझाईश दी गयी कि नशा उनके व उनके परिवार के भविष्य को खराब कर देगा और लोगों की समझाईश से प्रेरित होकर इन 8 युवकों द्वारा नशा बंदी की शपथ ग्राम संसद के दौरान ली गयी। मलगांव ग्राम संसद की यह दो घटनायें ग्रामसभाओं की सफलता को स्वयं बयान करती हैं।

• अभिषेक तिवारी

पुराने रेलवे ट्रेक पर सड़क बनाकर करेंगे विकास

ग्राम उदय से भारत उदय अभियान अंतर्गत आयोजित ग्राम संसदों के दौरान वैसे तो निर्माण कार्यों के कई प्रस्ताव तैयार किये गये हैं। ग्राम संसदों में खेत सड़क, सीसी रोड, शौचालय, पशुशेड, बीपीएल कार्ड, पात्रता पर्ची जैसे सामुदायिक एवं हितग्राहीमूलक कार्यों के कई प्रस्ताव ग्राम पंचायतों को मिलते हैं। परन्तु इन सबसे हटकर खण्डवा जिले के हरसूद विकासखण्ड की ग्राम पंचायत भवरली, पिपलानी, भराड़ी रैयत, तथा बड़खालिया के पंच सरपंच पर्यटन से अपने गांव के विकास के सपने देख रहे हैं। इन गांव के जनप्रतिनिधियों एवं ग्रामीणों को ग्राम संसद के आयोजन के दौरान पर्यटन से गांव का विकास करने के प्रस्ताव पर सहमति बनाने का अवसर मिला है। ज्ञात हो कि यह चारों पंचायतें नर्मदा सागर परियोजना अंतर्गत बने इंदिरा सागर डेम के बैक वाटर के समीप की पंचायतें हैं। इन पंचायतों के समीप से पहले कभी रेल गुजरा करती थी परंतु डूब में आ जाने के कारण यहां का रेलवे ट्रेक भी डूब गया है। अब इसी 10 कि.मी लम्बे पुराने रेलवे ट्रेक को ऊंचा उठाकर सड़क बनाने के प्रयास शुरू कर दिये गये हैं। ग्राम पंचायत भराड़ी के सरपंच नंदू राठौर बताते हैं कि बैक वाटर के अन्य क्षेत्रों में तो पानी सिमट जाता है लेकिन यह क्षेत्र ऐसा है जहां बांध में न्यूनतम लेवल होने पर भी सालभर पानी भरा रहता है। ज्ञात हो कि डूब में आने वाले पुराने हरसूद रेलवे फाटक से पिपलानी स्टेशन तक 10 किमी ट्रेक को ऊंचा उठाने और उस पर सड़क निर्माण की मांग व प्रस्ताव की तैयारी इन चारों ग्राम पंचायतों के द्वारा की गई है। इन चार पंचायतों के ग्रामीण दिन-रात हर साल जलमग्न होने वाले इस ट्रेक को देखते रहते हैं, उनका मानना है कि ट्रेक पर न्यूनतम 5 से 7 फिट और अधिकतम 25 से 30 फिट पानी रहता है ट्रेक की लम्बाई 8 से 10 कि.मी. है रेलवे ट्रेक को ऊंचा उठाकर सड़क निर्माण होने पर पर्यटन को एक नया आयाम मिलेगा।

• प्रीति नीखरा

सामूहिक विवाह सम्मेलन
सामाजिक समरसता की मिसाल बना गढ़ाकोटा

प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव की उपस्थिति में 25 अप्रैल को सागर जिले के गढ़ाकोटा में कन्या विवाह का पुण्य सामूहिक सम्मेलन सम्पन्न हुआ। इस समारोह में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव सहित राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों, स्थानीय जनप्रतिनिधियों तथा विशिष्ट विभूतियों ने शामिल होकर नवदम्पतियों को शुभाशीष प्रदान किया।

गढ़ाकोटा के कृषक स्टेडियम में सम्पन्न कन्या विवाह के सामूहिक सम्मेलन में पंचायत मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने कहा कि इस सामूहिक सम्मेलन को प्रारंभ हुए 15 वर्ष हो चुके हैं। यह 15वां पुण्य समारोह है जिसमें 16 मुस्लिम कन्याओं के निकाह उनकी धार्मिक परम्परानुसार मौलवियों के द्वारा सम्पन्न हो रहे हैं। इसके अलावा समाज की विभिन्न जातियों के कन्या विवाह वैदिक परम्परा से सम्पन्न हो रहे हैं। इस सम्मेलन में समाज के हर वर्ग व जाति को एक मण्डप में बैठकर परिणय बंधन में बांधने की परम्परा शुरू हुई है यह सामाजिक समरसता के लिए किया गया प्रयास है। इस आयोजन में हर जाति वर्ग के जोड़ों को एक समान सम्मान, भोजन, ठहरने एवं आने जाने की व्यवस्थाएं समान रूप से कराई हैं ताकि सभी वर्ग के लोग अपने को समान समझें। इस बात को ध्यान में रखकर पिछले वर्ष अपने इकलौते पुत्र व डॉक्टर पुत्री का विवाह सम्मेलन में अन्य गरीब कन्याओं के साथ कराकर दुगनी खुशी का अनुभव प्राप्त कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि 15 वर्षों से निरन्तर यह समारोह आगे बढ़ता जा रहा है। अपने लिये नहीं दूसरों के लिए परमार्थ करें वही सही जिन्दगी होती है। 50 हजार रुपये हमारे सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग द्वारा दिये जाते हैं। यहां विकलांगों का विवाह भी किया जा रहा है। श्री भार्गव ने कहा इस कार्य को जिन्दगी भर करता रहूंगा। उन्होंने सभी मित्रों को सहयोग देने के लिए धन्यवाद दिया। इस समारोह में कुल 562 कन्याओं का विवाह सम्पन्न हुआ। जिसमें 4 जोड़े निशक्तों के शामिल हैं वर एवं वधु दोनों विकलांग होने पर मंत्रीजी ने उन्हें एक लाख रुपये एवं वर एवं वधु दोनों में से एक विकलांग होने पर 50-50 हजार रुपये उपहार स्वरूप दिये। इस अवसर पर कलापथक दल द्वारा मनमोहक प्रस्तुतियां दी गईं।

गढ़ाकोटा में सम्पन्न कन्या विवाह के सामूहिक सम्मेलन में शुभाशीष देने जैव ऊर्जा प्रकोष्ठ श्री शैलेष केशरवानी, नगरपालिका अध्यक्ष श्री भरत चौरसिया, जनपद पंचायत अध्यक्ष श्री संजय दुबे, नगर पालिका उपाध्यक्ष श्री मनोज तिवारी, कलेक्टर श्री विकास नरवाल, पुलिस अधीक्षक श्री सचिन अतुलकर, जिला पंचायत सी.ई.ओ. श्री राजीव रंजन मीना, डॉ. के.के. खरे, पत्रकारगण, नवयुगल दम्पतियों के परिवारजन और बड़ी संख्या में नागरिक मौजूद थे।

ग्रामोदय से भारत उदय अभियान अब हर वर्ष आयोजित होगा

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने 28 अप्रैल को भोपाल में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए कलेक्टरों और कमिश्नरों के साथ ग्रामोदय से भारत उदय अभियान की समीक्षा करते हुए कहा है कि ग्रामोदय से भारत उदय अभियान का क्रियान्वयन पूरी गंभीरता और व्यवस्थित रूप से करें। यह जनता की समस्याओं का समाधान जमीनी स्तर पर करने का महत्वाकांक्षी अभियान है। इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी। अभियान में जनप्रतिनिधियों के सम्मान, संवाद और सहभागिता पर विशेष ध्यान दें। यह अभियान अब हर वर्ष आयोजित किया जायेगा। इस दौरान मुख्य सचिव श्री अँन्टोनी डिसा भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि अभियान में वातावरण निर्माण के विशेष प्रयास करें। जिन ग्रामसभाओं में उपस्थिति कम रही है वहां फिर से ग्रामसभाएं आयोजित करें। इस अभियान के दौरान ग्रामीण मिलकर विकास की योजनाएं बनायेंगे। यह विकेन्द्रीकरण का ऐसा प्रयोग है जिसमें जनता को निर्णय लेना है।

ग्राम सभाओं में हितग्राहीमूलक योजनाओं में पात्र हितग्राहियों की सूची बनायी जाये। अभियान को पूरी क्षमता और योग्यता से सफल बनायें। अभियान के दौरान आयोजित स्वास्थ्य शिविरों में चिन्हित की गयी संतानहीन महिलाओं के उपचार का व्यय मुख्यमंत्री स्वेच्छा अनुदान से किया जायेगा। इस दौरान कृषि के शामिल खातों के बंटवारे और आवासीय पट्टों के वितरण का अभियान भी चलायें। सभी अधिकारी अभियान के तहत ग्रामसभाओं में भागीदारी करें।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि अभियान में बेहतर काम करने पर प्रदेश स्तर पर तीन जिले, संभागस्तर पर तीन विकासखंड तथा जिलास्तर पर तीन ग्राम पंचायतों को पुरस्कृत किया जायेगा। मध्यप्रदेश देश का एकमात्र प्रदेश है जो इस अभियान को 45 दिन तक चला रहा है। अभियान में किये गये कार्यों की समय से रिपोर्टिंग करें। उन्होंने अभियान में की गई कार्रवाई की जिलेवार जानकारी ली। उन्होंने कहा कि इस दौरान जल संरचनाओं की मरम्मत और नये निर्माण की प्राथमिकता, कृषि की प्राथमिकता ग्रामस्तर पर तय करें। साथ ही प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के क्रियान्वयन की भी तैयारी करें। मुख्य सचिव श्री डिसा ने बताया कि अब अभियान के तहत 9 हजार 631 ग्राम संसद आयोजित की जा चुकी हैं।

नामान्तरण के 44 हजार 732, बंटवारे के 6 हजार 500 और सीमांकन के 3 हजार 820 प्रकरण निराकृत किये गये हैं। 11 हजार 94 स्वास्थ्य शिविर आयोजित किये जा चुके हैं। वीडियो कान्फ्रेंसिंग के द्वारा अपर मुख्य सचिव श्री एस.आर. मोहंती, अपर मुख्य सचिव श्री आर.एस. जुलानिया, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस सहित संबंधित विभागों के प्रमुख सचिव उपस्थित थे।

मध्यप्रदेश में वर्ष 2022 तक मुख्य सड़क से जुड़ेंगे

सभी गाँव

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मध्यप्रदेश के सभी ग्रामों को वर्ष 2022 तक मुख्य सड़क से जोड़ दिया जायेगा। उन्होंने कहा कि गाँव के विकास से ही देश का विकास होगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान 25 अप्रैल को इंदौर जिले के सांवेर विकासखण्ड के ग्राम बूढ़ी बरलाई की ग्रामसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि गाँव की सड़कों को मुख्य सड़क से जोड़ने की रणनीति तैयार कर ली गयी है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में पिछले 13 वर्ष में सभी क्षेत्र में विकास हुआ है। कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिये सिंचाई का रकबा बढ़ाया गया है। नर्मदा नदी को क्षिप्रा नदी से जोड़ा गया है। आने वाले समय में प्रदेश की अन्य प्रमुख नदियों को एक-दूसरे से जोड़े जाने का कार्य प्राथमिकता से किया जायेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 31 मई तक ग्रामोदय से भारत उदय अभियान निरंतर चलेगा। अभियान में न केवल ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान किया जायेगा, बल्कि सरकार की हितग्राहीमूलक योजना में हितग्राहियों का चयन किया जायेगा।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कृषि में अभूतपूर्व तरक्की की वजह से प्रदेश को पिछले 4 वर्ष से केन्द्र सरकार से कृषि कर्मण अवार्ड मिल रहा है। उन्होंने कहा कि किसानों को परम्परागत फसलों के उत्पादन के साथ-साथ फलों और फूलों की खेती की तरफ बढ़ना होगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार 2 लड़कियों वाले दम्पतियों को 55 साल की उम्र के बाद पेंशन देगी। निःसंतान महिलाओं को इलाज के लिये आर्थिक सहायता दी जायेगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में लाड़ली लक्ष्मी योजना से स्त्री-पुरुष के लिंगानुपात में भी सुधार हुआ है।

कार्यक्रम को विधायक श्री राजेश सोनकर ने भी संबोधित किया। बताया गया कि बूढ़ी बरलाई ग्राम पंचायत में पिछले 5 साल में करीब 4.25 करोड़ रुपये के विकास कार्य करवाये गये हैं। ग्राम के सभी 15 निःशक्तजन को प्रमाण-पत्र दिये जा चुके हैं।

तालाब

प्रदेश के देवास जिले की गोरवा ग्राम पंचायत एवं उसका जल संरक्षण कार्यक्रम पिछले दिनों उस समय चर्चा में आ गए जब खुद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में यहां के जल संरक्षण मॉडल का उल्लेख किया। महाराष्ट्र का लातूर इलाका पिछले कुछ दिनों से भीषण जल संकट के कारण सुर्खियों में है। वहां जल स्रोतों पर धारा 144 लागू की गई तथा दूसरे इलाकों से ट्रेन में भरकर पानी की आपूर्ति की गई। इस बात ने लातूर के किसानों के देवास प्रवास की स्मृतियां ताजा कर दीं जब गत वर्ष सितंबर माह में लातूर के 70 से अधिक किसानों ने टोंकखुर्द, गोरवा, हरनावदा आदि इलाकों में आकर न केवल लबालब भरे बलराम तालाबों के दीदार किए थे बल्कि इन तालाबों के निर्माण की तकनीक, इनसे उत्पादन में होने वाले इजाफे तथा निर्माण कार्य से जुड़ी अन्य तमाम जानकारियां भी हासिल की थीं। उन्होंने यह शपथ भी ली थी कि वे लातूर में भी देवास मॉडल को आधार बनाकर तालाब निर्माण का कार्य करेंगे।

आज हराभरा और खुशहाल देवास भी हमेशा से ऐसा नहीं था। एक वक्त ऐसा भी था जब देवास बूंद-बूंद पानी को तरस रहा था और पीने के लिए तथा औद्योगिक जरूरतों के लिए इंदौर से ट्रेन में भरकर पानी देवास पहुंचाया जा रहा था। दरअसल देवास औद्योगिक क्षेत्र है। बड़े पैमाने पर हैंडपंप लगने तथा औद्योगिक गतिविधियों का केंद्र होने के वजह से यहां भूजल का जमकर दोहन किया गया। आखिरकार औद्योगिक इकाइयां बिना पानी के ठप हो गईं। जल स्तर 500 से 700 फीट तक नीचे चला गया। तब देवास कलेक्टर के रूप में पदस्थ आईएएस श्री उमाकांत उमराव ने क्षेत्र में पानी की कमियों की वजह की पड़ताल करने की कोशिश की। पता लगा कि नलकूपों के जरिए अधिकांश भूजल का दोहन कर लिया है। लेकिन क्षेत्र में पर्याप्त मानसूनी बारिश होने के बावजूद वह भूजल रिचार्ज नहीं हो पा रहा है। उमराव ने फैसला किया कि स्थानीय किसानों को इस बात के लिए मनाया जाए कि वे अपने खेतों के दसवें हिस्से में तालाब बनाकर वर्षा जल का संरक्षण करें। वह अधिकारियों के साथ गाँव-गाँव जाते और किसानों से बात करते। निपानिया गाँव के पोप सिंह राजपूत नामक किसान को उमराव ने अपनी गारंटी पर 14 लाख रुपए का बैंक ऋण दिलवाया। इससे राजपूत ने 10 बीघे का विशालकाय तालाब बनवाया। नतीजा, पहले केवल सोयाबीन की फसल लेने वाले राजपूत अब साल में दो फसल लेने लगे। उन्होंने न केवल बैंक का कर्ज चुका दिया बल्कि कुछ ही वर्षों में 10 बीघे और खेत खरीद लिए। इस बीच जल संरक्षण और तालाब निर्माण का देवास मॉडल प्रदेश क्या, देश भर में चर्चित हो गया।

देवास और उसके आसपास के इलाकों में जो हरियाली नजर आती है, वहां के किसानों में जो बेफिक्री देखने को मिलती है। उसका बहुत अधिक श्रेय मध्यप्रदेश शासन द्वारा शुरू की गई रेवासागर एवं बलराम तालाब योजना को भी जाता है। अप्रैल 2008 से शुरू की गई इस योजना के तहत किसानों को अपने खेत पर तालाब तैयार करने के लिए 80,000 रुपये तक का अनुदान दिया जाता है। ये तालाब न केवल वर्षा जल को धारण करते हैं बल्कि इनकी वजह से आसपास के इलाकों का जल स्तर भी बरकरार रहता है। तालाब की गाद खेतों में डालने पर खाद का काम करती है और पानी का स्तर बढ़िया होने के कारण जलस्तर में भी इजाफा होता है। योजना के मुताबिक तालाब की कुल लागत का 25 प्रतिशत और अधिकतम 80,000 रुपये तक की राशि किसान को तालाब निर्माण के लिए प्रदान की जाती है।

गोरवा बना गौरव का विषय - यूं तो प्रदेश के सभी जिलों के सभी वर्गों के किसानों को इस योजना का लाभ मिल रहा है लेकिन हमें इसका वास्तविक या कहें जमीनी परिणाम देखने को मिला मध्यप्रदेश के देवास जिले के कई गांवों में। गोरवा ग्राम पंचायत का जिक्र तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद गत 24 अप्रैल को प्रसारित अपने मन की बात कार्यक्रम तक में किया। गोरवा गांव की यात्रा के दौरान इस सफलता के दीदार हुए। टोंक खुर्द तहसील में आने वाला यह गांव तालाबों के सहारे सफलता की नई दास्तान लिख रहा है। तालाब और पानी किस तरह लोगों की किस्मत बदल सकते हैं, यह गांव इसका जीता जागता उदाहरण है। करीब 1500 की आबादी वाले इस गाँव में वर्ष 2006 तक पानी की कमी बहुत बड़ी समस्या थी। उस समय गाँव के एक दो सम्पन्न किसानों के पास ट्रेक्टर थे लेकिन खेती से उपज इतनी ही होती जिससे बमुश्किल पेट पाला जा सके। बरसात के अलावा गर्मियों और जाड़ों में पानी के लिए केवल किस्मत ही एकमात्र सहारा थी। लेकिन तत्कालीन कलेक्टर श्री उमाकांत उमराव और बाद में बलराम तालाब योजना के सार्थक इस्तेमाल ने गोरवावासियों की तकदीर बदल दी। 10 साल पहले की तुलना में आज गांव की तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। आज गाँव के लगभग हर किसान के खेत में अपना तालाब है। इन तालाबों से ही मिला हौसला है जो कि कुछ किसान अब ग्रीनहाउस की मदद से खेती कर रहे हैं। सामान्य खेती के अलावा नकदी फसलों पर जोर बढ़ा है। गाँव के पूर्व सरपंच राजाराम पटेल बताते हैं कि आज गोरवा गाँव में कुल ट्रेक्टरों की संख्या बढ़कर 150 के करीब पहुंच गई है। यानी हर 10 गांववालों में

से बदली तस्वीर!

से एक के पास अपना ट्रेक्टर है। ये ट्रेक्टर न केवल खेती में मदद करते हैं बल्कि आसपास के गाँवों में तालाब खोदने में भी मददगार साबित होते हैं। राजाराम बताते हैं कि आज भी गाँव में या आसपास खुदने वाले किसी भी तालाब में पहली कुदाल चलाने के लिए श्री उमाकांत उमराव को याद किया जाता है और वह बकायदा आते हैं।

आईएएस अधिकारी अगर किसानों को खुद आगे बढ़कर फोन करें और उनके खेतों में कुदाल चलाएं तो भला किसानों को प्रेरणा क्यों न मिले। गोरवा के दो किसानों को जल संसाधन मंत्रालय की ओर से भूमि जल संवर्द्धन पुरस्कार भी मिल चुका है।

इतना ही नहीं इस योजना की सफलता ने देश भर के किसानों को अपनी ओर आकर्षित किया है। लातूर के किसानों का जिक्र हम ऊपर देख चुके। इसके अलावा बुंदेलखंड के उत्तर प्रदेश में आने वाले इलाकों में भी किसान अपना तालाब योजना के तहत खेत तालाब बना रहे हैं। अपना तालाब अभियान के संयोजक पुष्पेंद्र भाई कहते हैं कि देवास का अनूठा मॉडल देखने के बाद ही उनके दिमाग में यह बात आई कि बुंदेलखंड में भी तालाब बन सकते हैं।

उन्होंने यह बात प्रदेश के सरकारी अमले तक पहुंचाई और अब उत्तरप्रदेश सरकार भी बुंदेलखंड इलाके में करीब 2,000 तालाब खोद रही है। बलराम तालाब के लिये अनुदान प्राप्त करने की खातिर भी राज्य शासन ने विशिष्ट दिशा-निर्देश जारी किये हैं। इसके लिए आवेदक किसान को अपने क्षेत्र के कृषि विस्तार अधिकारी के समक्ष निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना होगा। योजना के तहत 50 प्रतिशत तक कार्य पूरा हो जाने के बाद अनुदान की पहली किश्त जारी करने की अनुशंसा की जाएगी। पहली किश्त के भुगतान के बाद तीन महीने के भीतर किसान को काम पूरा करना होगा। जब काम पूरी तरह समाप्त हो जाएगा तो शेष राशि का भुगतान भी कर दिया जाएगा। यह पूरा लेनदेन बैंक के जरिये किया जाएगा। यदि किसान ने तालाब खोदने के लिए ऋण लिया है तो ऋण वसूली का काम दो साल की अवधि के बाद ही शुरू किया जाएगा। नियमानुसार सात साल के भीतर ऋण राशि की पूरी अदायगी करना आवश्यक होगी। ऋण राशि में से अनुदान राशि को अलग करने के बाद ही ब्याज की गणना की जाएगी। इसी के आधार पर किश्तों का निर्धारण भी किया जाएगा।

आखिर क्या है देवास तालाब मॉडल- वर्तमान में उच्च शिक्षा आयुक्त के पद पर पदस्थ आईएएस श्री उमाकांत उमराव ने देवास कलेक्टर रहते हुए इस मॉडल की शुरुआत की थी। पेशे से सिविल इंजीनियर श्री उमराव कहते हैं कि सामान्य तौर पर इस मॉडल में कुछ भी खास नहीं लगता। लगता है कि किसान अपने खेतों में छोटे-मोटे तालाब ही तो खोदते रहे हैं।

प्रश्न यह था कि पर्याप्त बारिश के बावजूद हमारा भूजल स्तर बरकरार क्यों नहीं रह पाता। गाँव-गाँव में खोदे गए यही तालाब भूजल रिचार्ज का अहम जरिया बने। बारिश की अत्यंत कमी वाले कुछ क्षेत्रों को छोड़ दें तो पूरे देश में वर्षा जल हमारी सिंचाई की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। हर 100 लीटर वर्षा जल में महज 10 से 15 लीटर पानी ही नदियों और बांधों में जा पाता है। अगर हम इन 100 लीटर में से 20-30 लीटर पानी को नदियों और भूजल तक पहुंचा सकें तो यह बहुत अहम होगा। इजरायल जैसे देश में यह स्तर प्रति 100 लीटर में 62 लीटर है।

श्री उमराव ने सोचा कि वर्षा जल प्रबंधन का मॉडल ऐसा हो ताकि किसानों की लाभ की इच्छा पूरी हो। उन्हें लगे कि अगर वे तालाब खोदते हैं उसका सीधा फायदा किसानों को मिले। इससे पहले जहां सरकारी नारे 'जल ही जीवन है, कि अवधारणा पर केंद्रित रहते थे वहीं हमने उसे 'जल बचाइए, लाभ कमाइए' में तब्दील कर दिया।

ऐसा इसलिए क्योंकि लाभ की अवधारणा मनुष्य को बहुत जल्दी समझ में आती है... 'तालाब निर्माण की इस योजना ने प्रदेश के कई किसानों की तकदीर तो बदली ही है। निरंतर सूखे और पानी के भीषण संकट के इस दौर में यह योजना देश के ग्रामीण अंचलों को एक नई राह भी दिखा सकती है।

• **पूजा सिंह**

अपना सारा काम छोड़ मुख्यमंत्री उज्जैन पहुंचे

वह अक्षय तृतीया का दिन था। भगवान परशुराम का अवतार दिवस और उज्जैन सिंहस्थ में शाही स्नान का पर्व। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान एक दिन पहले ही उज्जैन की व्यवस्थाओं का जायजा लेकर भोपाल लौटे थे। इसमें पहले दोनों स्नानों में उन्होंने उज्जैन में डुबकी लगाई थी। इसीलिए अक्षय तृतीया पर उन्होंने भोपाल में रहने का निर्णय लिया था। इस दिन उनके तमाम प्रमुख कार्यक्रमों में से सबेरे केंद्रीय मंत्री राम माधव से भेंट और शाम को भोपाल के परशुराम मंदिर के कार्यक्रमों में जाना निश्चित था। मंदिर में ब्राह्मणों के विभिन्न संगठनों में समन्वय का काम करने वाली संस्था ब्रह्म संसद ने शोभायात्रा का आयोजन किया था। मुख्यमंत्री श्री चौहान इस यात्रा की अगवानी और भगवान परशुरामजी की आरती करने वाले थे। दोपहर दो बजे तक सब ठीक था लेकिन दोपहर में अचानक बादल घुमड़ आए और बादल, आंधी, पानी ने सिंहस्थ की तमाम व्यवस्थाओं को बिखेर दिया।

तब श्री चौहान अपने निवास पर थे और भोजन की तैयारी कर रहे थे। समाचार सुना तो भोजन छूट गया। उन्होंने ताबड़ तोड़ विवरण लिया और अधिकारियों को व्यवस्था के लिए सतर्क किया तथा अपने सहयोगी अधिकारियों को भोपाल एयरपोर्ट भेजा ताकि वे स्वयं भी शीघ्र उज्जैन जा सकें। लेकिन मौसम इतना खराब था कि हवाई जहाज के पायलटों ने हाथ खड़े कर दिए। मौसम की लगातार अप्रिय खबरों से वे इतने बैचेन हुए कि सड़क मार्ग से ही उज्जैन रवाना हो गए। वे बंगले से निकलकर पहले शिवाजी नगर स्थित भगवान परशुराम मंदिर गए भगवान के दर्शन किए, ब्राह्मण समाज के जो भी प्रतिनिधि मिले उनसे शाम को न आ सकने की अपनी विवशता बताई और तेजी से उज्जैन रवाना हो गए।

वे सड़क मार्ग से उज्जैन पहुंचे। उन्होंने रास्ते में ही अधिकारियों को हिदायत दे दी थी कि उनसे मिलने में समय व्यर्थ न करें तथा वे राहत के काम में लगे रहें। यह मुख्यमंत्री की चिंता थी, उनकी चुस्ती थी कि पूरा प्रशासन, तमाम सामाजिक कार्यकर्ता और उज्जैन के स्थानीय नागरिक बचाव एवं सेवा-सहायता कार्यों में जुट गए। वे रात को ही उन पंडालों में पहुंचे जहां ज्यादा नुकसान हुआ था। वे उन घाटों पर भी गए जहां ड्रेनेज टूटकर पानी सीधा क्षिप्रा में आ गया था। सुधार और राहत के काम रातभर चले और शिवराज जी भी जागकर लोगों को सांत्वना देते नजर आए देश विदेश के श्रद्धालु और संत राज्य के मुखिया को अपने बीच पाकर संतुष्ट हुए तथा राहत सहायता में सहयोग करने लगे।

आम आदमी की तरह शिविर में फावड़ा चलाया

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान सिंहस्थ मेला क्षेत्र में तेज बारिश एवं आँधी से क्षतिग्रस्त शिविरों और आश्रमों में पहुँचे। उन्होंने आँधी से प्रभावित हुए पंडालों एवं संत शिविरों को पुनः खड़ा करने में आम आदमी की तरह मदद की। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री श्री चौहान के साथ ही उनकी धर्मपत्नी श्रीमती साधना सिंह ने भी शिविर, पंडालों में चूरी की

तगाड़ी भरकर डाली। टेंट खड़ा करने के बाद मुख्यमंत्री ने स्वयं गद्दे बिछाये और संतों को बुलवाया।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने मंगलनाथ क्षेत्र के प्लॉट नम्बर 373 पर श्री रामरायदासजी महाराज के शिविर में करीब 25 मिनट तक रुककर श्रमदान किया। उन्होंने अपने साथ मौजूद जन-प्रतिनिधियों तथा अधिकारियों से श्रमदान भी करवाया। इस दौरान मुख्यमंत्री की वाणी काफी सहज, विनम्र और आम आदमी की तरह लग रही थे। वे एक आदमी की तरह वाक्यांश जैसे 'सब काम करो रे' रस्सी अच्छे तरीके से बाँधना 'गाँठ भी ठीक से लगाओ' बोलकर उपस्थितजनों को श्रमदान के लिये प्रेरित कर रहे थे।

आश्रमों में श्रमदान किया

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सिंहस्थ महापर्व के दौरान आँधी-तूफान से संत-महात्मा के तबाह हुए आश्रमों में जाकर संतों की सेवा और श्रमदान का जो मौका मिला है उसे वे गवांना नहीं चाहते। मुख्यमंत्री सिंहस्थ मेला क्षेत्र के विभिन्न आश्रमों में श्रमदान कर रहे थे। इस मौके पर उनकी पत्नी श्रीमती साधना सिंह भी उनके साथ थीं उन्होंने भी श्रमदान किया और संतों की सेवा की।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि सिंहस्थ में देशभर के संत-महात्मा उज्जैन आए हैं। उनके आशीर्वाद से सिंहस्थ सफलतापूर्वक सम्पन्न होगा।

उन्होंने कहा कि क्षतिग्रस्त आश्रमों को सबके सहयोग से मिलकर जल्द ठीक किया जाएगा। श्री चौहान ने कहा कि राज्य सरकार का पूरा प्रयास है कि देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की तकलीफ न हो।

श्रमदान के दौरान श्री चौहान रामतपेश्वरदास महाराज जनकपुर धाम नेपाल के आश्रम, श्री बलरामदास महाराज वृन्दावन, रामपदारथ दास जूनागढ़ गुजरात, गौरेदाउ राधे राधे बाबा, हरिनारायण संतोषी खालसा, अखिल भारती निर्मोही राधे-राधे बाबा, बनखंडी शक्तिपीठ कालीधाम जालोन, अंजनी अन्नपूर्णा क्षेत्र और उज्जैन खालसा आश्रम पहुँचे तथा संत-महात्माओं से बातचीत की। मुख्यमंत्री ने अयोध्या के संत नृत्यगोपालदास महाराज से छोटी छावनी अयोध्या आश्रम स्थित उनकी कुटी में पहुँचकर आशीर्वाद लिया। अंत में मुख्यमंत्री रावतपुरा सरकार के आश्रम पहुँचे और संत रविशंकर महाराज से चर्चा की।

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान दो दिन पहले अर्धरात्रि में होमगार्ड की नाव से आकस्मिक रूप से रामघाट पहुंचे थे और उन्होंने भ्रमण कर सिंहस्थ की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मुख्यमंत्री श्री चौहान पर जब श्रद्धालुओं की नजर पड़ी, तो वे सब हतप्रभ थे। घाट के किनारे स्नान कर रहे बच्चे मामा-मामा की आवाज देकर हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहे थे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान भी पर्व स्नान में आये देश के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों का अभिवादन कर रहे थे। उन्होंने भ्रमण के दौरान घाटों की साफ-सफाई, सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने रामघाट स्थित श्री पंचायती बड़ा उदासीन अखाड़े में जाकर श्री महंत ब्रह्म श्री महाराज पूर्व अध्यक्ष पंचायती अखाड़ा से आशीर्वाद प्राप्त किया। उन्होंने संतों के साथ भोजन प्रसादी भी ग्रहण की।

सेवा और श्रद्धा की आपदा पर जीत

यह समाज और सरकार की सेवा एवं सिंहस्थ में आए तीर्थ यात्रियों की श्रद्धा का कमाल ही था कि आपदा ने स्नान में मुश्किलें तो खड़ी कीं किंतु आस्था को डिगा नहीं सकी। लोग बरसते पानी और तेज हवाओं के बीच भी स्नान करते रहे। महाकाल के दर्शन की कतार में लगे रहे। यही नहीं जिन संतों की यात्राएं निकलनी थीं वे भी निकलीं। हां शाम को प्रवचन एवं अन्य सामाजिक, सांस्कृतिक तथा बौद्धिक आयोजन जरूर प्रभावित हुए।

अक्षय तृतीया को शाही स्नान

श्री पंच दशनाम जूना अखाड़ा- यह अखाड़ा स्नान के लिए भूखी माता स्थित छावनी से जुलूस के रूप में प्रातः 3.20 रवाना होकर 4 बजे दत्त अखाड़ा घाट पर पहुंचा और स्नान के बाद पुनः अपनी छावनी के लिए रवाना हुआ। जूना अखाड़ा के साथ हनुमानगढ़ी के पास से आवाहन एवं अग्नि अखाड़े बड़नगर रोड होते हुए भूखी माता मार्ग पर जूना अखाड़े के जुलूस में शामिल होकर स्नान के लिए प्रातः 4 बजे दत्त अखाड़ा पर पहुँचे और स्नान कर दत्त अखाड़ा से वापस भूखी माता मार्ग होते हुए बड़नगर मार्ग से वापस अपने कैम्प के लिए रवाना हुए।

श्री तपोनिधि निरंजनी अखाड़ा एवं श्री पंचायती आनंद अखाड़ा- श्री निरंजनी अखाड़ा एवं पंचायती आनंद अखाड़ा बड़नगर रोड स्थित अपनी छावनी से निकलकर शंकराचार्य चौक से छोटी रपट, दत्त अखाड़ा घाट पर प्रातः 5 बजे पहुँचकर स्नान किया। इसके बाद पुनः उसी मार्ग से अपनी छावनी के लिए रवाना हुआ।

श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा एवं पंच अटल अखाड़ा- श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा एवं पंच अटल अखाड़ा बड़नगर रोड छावनी से शंकराचार्य चौक होते हुए छोटी रपट, केदारघाट एवं दत्त अखाड़ा घाट पर प्रातः 6 बजे पहुँचकर स्नान किया और पुनः इसी मार्ग से छावनी की ओर रवाना हुआ।

शाही स्नान में अखाड़ों के सभी महामण्डलेश्वर एवं खालसों ने शामिल होकर अपने अखाड़ों के साथ स्नान किया। अखाड़ों के लिए निर्धारित समय में रामघाट व दत्त अखाड़ा घाट पर आम श्रद्धालुओं का स्नान के लिए प्रवेश प्रतिबंधित रहा। अखाड़ों के स्नान के बाद ही आम श्रद्धालु इन घाटों पर स्नान के लिए पहुँचना शुरू हो गए और देखते ही देखते रामघाट पर आस्था और विश्वास का जन सैलाब शाही स्नान में अमृतपान के लिए उमड़ पड़ा। आस्था और विश्वास का यह नजारा देखते ही बन रहा था।

निर्वाणी अखाड़े के साधु-संतों ने रामघाट में आस्था एवं भक्ति से ओतप्रोत होकर क्षिप्रा में अमृत की डूबकी लगाई। संत-महात्मा, साधु-संत, पथ-प्रदर्शक ने दौड़ते हुए महादेव के जयकारे के साथ सामूहिक स्नान किया। अखाड़ों के नागा साधुओं के स्नान का दृश्य राम घाट पर विशेष आकर्षण का केन्द्र रहा। शाही स्नान में आस्था, अमृत और आत्मा का अनोखा संगम देखने को मिला।

रामघाट का अनोखा एवं विहंगम दृश्य साधु-संतों एवं महात्माओं का सामुहिक अमृत स्नान भगवान शिव की महिमा से अच्छादित सा हो गया था। श्री पंच निर्वाणी अखाड़ा के महंत श्री धर्मराज श्री महाराज के साथ सैकड़ों

साधु-संतों ने क्षिप्रा आरती द्वार पर मोक्ष दायिनी क्षिप्रा में अमृत स्नान किया। श्री निर्मोही अणि अखाड़ा, निर्वाणी अणि अखाड़ा, दिगम्बर अणि अखाड़ा, श्री पंचायती उदासीन बड़ा अखाड़ा, श्री पंचायती नया उदासीन अखाड़ा तथा श्री निर्मल अखाड़ा के साधु-संतों ने रामघाट में शाही स्नान किया। शाही स्नान के लिए पंच निर्वाणी अखाड़ों के साधु-संत टेक्ट्रर ट्राली एवं अन्य वाहनों में सजे रथों पर सवार थे। छत्र और चँवर के साथ इन रथों का आकर्षण देखते ही बनता था। पंच निर्वाणी अखाड़े के युवा साधु-संत विभिन्न शस्त्र कलाओं का प्रदर्शन भी कर रहे थे। वही बुजुर्ग साधु-संतों को गोद में लेकर गुरू-शिष्य परम्परा को जीवंत किया। रामघाट पहुँचने पर सर्वप्रथम आयुक्त नगर-निगम एवं मेला अधिकारी श्री अविनाश लावानिया सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने पुष्पहार भेंट कर अखाड़ों के साधु-संतों का स्वागत किया।

तीर्थ पुरोहित पंडित विजय त्रिवेदी रतलामी ने पंच निर्वाणी अखाड़ों की पूजन विधि सम्पन्न कराई। श्री लावानिया और श्री महंत धर्मराज जी महाराज ने शाही पूजन किया। पूजन के बाद श्री लावानिया ने महंत श्री धर्मराज जी महाराज और पंडित विजय त्रिवेदी को चाँदी का सिक्का भेंट किया। इसके बाद दिगम्बर अखाड़े के साधु-संत अपने अनुयायी साधु-संतों के साथ रामघाट आरती द्वार पहुँचे। अखाड़े के सभी संतों ने मोक्षदायिनी सलिला क्षिप्रा में उत्साह के साथ स्नान किया।

तीनों अणि अखाड़ों का जुलूस मेला क्षेत्र के मुख्य मार्गों से गुजरा, तो चप्पे-चप्पे में ईश्वर की आराधना, गीतों एवं भक्ति से जय-जयकार गुँजायमान हो रहा था।

धर्म एवं आस्था का समागम सिंहस्थ कुभ महापर्व का दूसरा शाही स्नान मोक्षदायिनी क्षिप्रा सलिला के रामघाट, दत्त अखाड़ा, सहित विभिन्न घाटों में संपन्न हुआ। शाही स्नान में क्षिप्रा सलिला में डुबकी लगाने के लिए साधु-संत एवं महात्माओं की भीड़ उमड़ पड़ी। शाही स्नान के दौरान साधु-संत एवं महात्माओं ने विधि-विधान के साथ पूजा-अर्चना की और मोक्षदायिनी क्षिप्रा सलिला में जय-जयकार के नारे लगाते हुए धर्म एवं आस्था की डुबकी लगाई।

इसके साथ ही शाही स्नान में लाखों श्रद्धालुओं ने भी डुबकी लगाकर पुण्य-लाभ प्राप्त किया। डुबकी लगाने वाले श्रद्धालुओं में धर्म और आस्था के प्रति गहरा लगाव देखने को मिला। शाही स्नान के दौरान साधु-संतों और महात्माओं के दौड़ते हुए क्षिप्रा में आकर डुबकी लगाने के दृश्य ने सभी को सम्मोहित किया।

● **रमेश शर्मा**

परमात्मा की शक्ति औ

हम परमात्मा को कभी देख नहीं सकते, उनसे मिल नहीं सकते। देखा उसे जा सकता है जो बाहर हो, पृथक हो। मिला उससे जा सकता है जो द्वैत हो, दूसरा हो। लेकिन परमात्मा तो अद्वैत है, हमारे भीतर है, हमसे अलग नहीं है। मछली कभी सागर को नहीं देख सकती, चूंकि वह सागर के भीतर है, सागर में ही समाई है इसीलिए वैदिक ऋषि ने उद्घोष किया कि "अहम् ब्रह्मस्मिं। अर्थात् मैं भी ब्रह्म हूं। यदि परमात्मा संपूर्ण सृष्टि में व्यापा हुआ है तो मैं परमात्मा के भीतर हूं, बिल्कुल सागर में मछली की तरह। और यदि परमात्मा मेरे भीतर है तो वह रग-रग में व्यापा हुआ है फिर भी नहीं देख पाऊंगा यदि मैं भी ब्रह्म हूं, उसी परम ब्रह्म परमात्मा का अंश हूं तब उसे देख कैसे पाऊंगा। बस उसका आभास कर सकता हूं। अपने ही भीतर अथवा अपने जैसे उन प्राणियों के भीतर भी जो मेरे ही जैसे हैं जिनका निर्माण उन पंच महाभूतों से हुआ है जो सृष्टि के प्रत्येक कण में मौजूद है, उन्हीं से मैं बना हूं और उसी से बांधा हुआ, वही सबके भीतर मौजूद केन्द्रीयभूत शक्ति है और वही संचालित कर रहा है इस संपूर्ण सृष्टि को और समस्त प्राणियों को और मैं भी उसी से संचालित हूं जो मेरे भीतर है और इसी का आभास मुझे उस दिन उज्जैन के सिंहस्थ महाकुंभ में हुआ।

वह अक्षय तृतीया के महापर्व की तिथि थी पुराणों के अनुसार अक्षय तृतीया नारायण के छठे अवतार भगवान परशुराम के अवतरण की तिथि। माना जाता है कि वह अवतार अक्षय है इसीलिए अवतार तिथि अक्षय कहलाई। अक्षय का संबंध अमृत से भी है। मान्यता है कि अमृत पान अथवा अमृतमयी जल के स्नान से प्राणी अमर हो

र संचेतना का आभास

जाता है, अक्षय हो जाता है। महापर्व में अक्षय तृतीया को स्नान करने से पुण्य अक्षय हो जाते हैं। पुण्यों के अक्षय हो जाने का अर्थ है संसार के आवागमन से मुक्ति। इसीलिए अक्षय तृतीया को सिंहस्थ स्नान करना अति महत्वपूर्ण माना गया। यही भाव लेकर मैं उस दिन उज्जैन गया था। ठहरने, स्नान, दर्शन आदि में कोई कठिनाई नहीं हुई लेकिन जैसे ही दर्शन करके बाहर आया मौसम बिगड़ गया। अचानक बादलों की गरज, तेज आंधी और पानी की बौछारें। यह सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि किसी को संभलने का, या कहीं सुरक्षित स्थान पर छिपने का अवसर ही न मिला और यदि अवसर मिलता तब भी शायद छिपने का स्थान न मिलता चारों ओर जनसैलाब। मैं ठीक से नहीं कह सकता हूं फिर भी अनुमान है कोई दस लाख लोग सड़क पर और घाटों पर होंगे। इतने लोगों को छिपने की कोई संभावना नहीं, कोई स्थान नहीं और न अवसर, बादलों ने सूरज को ढंक लिया था, आंधी और आंधी के साथ धूल भरी बरसात मानों बरबस पलकों से आंखों को भी ढांक रही थी सड़कों पर जाम लग गया था। उज्जैन का ड्रेनेज सिस्टम जाम हो गया। नालियों की सारी गंदगी सड़कों पर और सड़कों से घाट पर जाने लगी। जहां लाखों लोग डुबकी लगा रहे थे। सड़कों पर कारों और अन्य वाहनों का इतना जाम लगा कि पैदल चलते श्रद्धालुओं का चलना मुश्किल। फिर भी कोई तनाव नहीं, कोई विचलन नहीं।

जो लोग घाटों पर थे, डुबकियां लगा रहे थे, उन्हें इसकी परवाह नहीं थी कि घाटों पर नाली का पानी आ गया था, या आसमान में बादल गरज रहे हैं और बिजली चमक रही है। इसी महाकुंभ के पहले स्नान में मंगलनाथ में ऐसी घटना घट चुकी थी। बरसात में गिरने वाली बिजली का दुष्प्रभाव सैकड़ों गुना होता है लेकिन किसी को परवाह नहीं, किसी को भय नहीं। सबके मन में वही श्रद्धा थी जिसे संजोकर वे अपने घर से चले गए थे। उनका सारा सामान भीग गया था। स्नान के बाद उन्हें जो साफ-सूखे कपड़े पहने थे वे भी भीग गए थे फिर भी वे अविचलित थे और उसी अवस्था में भगवान महाकालेश्वर के दर्शन को चल दिए। उनके कदमों को, उनकी चाल को, उनकी आस्था कोई डिगा नहीं पा रहा था।

आस्था की आंखों और श्रद्धा की शक्ति से वह अपार समूह सड़कों पर मानों रेंग रहा

का श्रद्धालुओं की आस्था और विश्वास पर कोई असर नहीं पड़ा। श्रद्धालु अक्षय तृतीया की देर रात तक मोक्षदायिनी क्षिप्रा में डुबकी लगाकर पुण्य-लाभ प्राप्त करते रहे। देश के कोने-कोने से आए श्रद्धालु पुण्य-स्नान के बाद यह कहते सुने गये कि यदि व्यवस्थाएँ अच्छी न होतीं तो शायद ही हम क्षिप्रा में स्नान कर पाते।

आंध्रप्रदेश के वाई मोहनराव अपनी सास, धर्मपत्नी एवं अन्य परिजनों के साथ सिंहस्थ में स्नान के लिए आये हैं। उनका कहना था कि जैसे ही उज्जयिनी की धरती पर कदम रखा वैसे ही बारिश और आँधी शुरू हो गई, इससे चिंता हुई कि अब कैसे स्नान होंगे। एक ओर मन में विश्वास था तो दूसरी ओर सिंहस्थ परिसर के इन्तज़ाम बेहतर मिले। फिर क्या बारिश थमते ही हम पवित्र रामघाट की ओर बढ़े। उनका कहना था हालांकि अक्षय तृतीया का पुण्य नक्षत्र होने से श्रद्धालुओं का भारी हुजूम सिंहस्थ मेला परिसर में समाया हुआ था, इसलिए मुझे परिवार सहित रामघाट पर पहुँचने में थोड़ा ज्यादा वक्त लगा। पर रामघाट पर मोक्षदायिनी क्षिप्रा में डुबकी लगाते ही हमारी सारी थकान दूर हो गई। झारखण्ड में निजी कारोबार कर रहे ग्वालियर निवासी राकेश चौहान जब इंदौर पहुँचे थे, तभी उन्हें पता लगा कि मेला क्षेत्र में आँधी और बारिश आ गई है। उन्होंने आस्था एवं विश्वास पर अपनी यात्रा जारी रखी तथा देर रात रामघाट पहुँचकर क्षिप्रा में डुबकी लगाई। भिण्ड जिले के ग्राम मुरावली से आये महेन्द्र कौरव भी आँधी और बारिश के बाद उज्जैन पहुँचे थे और उन्होंने गऊ घाट पर पवित्र सलिला क्षिप्रा में अपनी पत्नी के साथ डुबकी लगाकर सिंहस्थ स्नान का वर्षों पुराना सपना पूरा किया। ये सभी श्रद्धालु सिंहस्थ में मध्यप्रदेश सरकार द्वारा की गई व्यवस्थाओं की तारीफ करते हुए नहीं थक रहे थे।

और सरकारी अमले की चुस्ती

बे-मौसम बारिश एवं आंधी से पूरे सिंहस्थ मेला क्षेत्र के पंडालों और आम रास्तों में भरे पानी को मेला प्रबंधन द्वारा तत्परता से खाली करवाया गया है। क्षतिग्रस्त पंडालों को मूल-स्वरूप में लाने में भी शासकीय अमले द्वारा साधु-संतों को पूरा सहयोग दिया जा रहा है। बारिश से मेला क्षेत्र के मार्ग में हुए कीचड़ सफाई का काम तत्परता से किया गया है। जरूरत के मुताबिक जगह-जगह पर कीचड़ वाले क्षेत्रों में बजरी इत्यादि डलवाई गई है। शासकीय अमले की अथक मेहनत की बदौलत पंडाल व मार्ग अपने मूल स्वरूप में लौट रहे हैं। सभी तरह की बुनियादी सुविधाएँ भी बहाल कर दी गईं। मेला क्षेत्र में भर गये पानी को खाली करवाने में मशीनों की भी मदद ली गई। दत्त अखाड़ा जोन क्षेत्र के

अंतर्गत शंकराचार्य से दत्त अखाड़ा घाट मार्ग, भूखीमाता रोड, खेड़ापति सरकार, विष्णुनारायण दण्डी आश्रम, सर्वधर्म सनातन महासभा आदि समेत मंगलनाथ क्षेत्र के विभिन्न सेक्टर के पंडालों और मार्ग में भरे पानी को खाली करवाया गया है, जिनमें दत्त अखाड़ा घाट मार्ग पर स्थित श्री पंचदशनामी 13 मढ़ी प्रवेश द्वार सहित अन्य पंडाल शामिल हैं। जेसीबी सहित अन्य मशीनों एवं कर्मचारियों की मदद से मार्गों और पंडालों की कीचड़ भी साफ करवाई गई है कीचड़ से निजात पाने के लिए जगह-जगह छोटी गिट्टी और बारीक बजरी डलवाई है। सड़क मार्गों पर समतलीकरण के लिए विभिन्न मार्ग पर रोलर भी चलवाए।

विद्युत अमले द्वारा ऐहतियात बतौर पंडालों में जाकर भीतरी एवं बाहरी क्षेत्र की विद्युत लाईनों की जांच व मरम्मत की गई। नगर-निगम व पीएचई के अमले द्वारा बे-मौसम बारिश से प्रभावित सीवर लाईनों को तत्परता से दुरुस्त किया गया है। इसी तरह पेयजल आपूर्ति व्यवस्था में आई रुकावटों को दूर किया गया है। शौचालयों की सफाई करवाकर आसपास ब्लीचिंग पॉउडर का छिड़काव करवाया गया।

● **मुकुरिता दुबे**

सिंहस्थ
कुंभ महापर्व 2016
विक्रम संवत् 2073

स्वच्छ भारत की परिकल्पना को साकार कर रहा है

सिंहस्थ कुंभ महापर्व

महाकाल की पावन नगरी उज्जैन में क्षिप्रा की अमृत बूंदों का स्पर्श।

उज्जैन सिंहस्थ मेला क्षेत्र हो या उज्जैन का बाहरी क्षेत्र हो, लाखों व्यक्तियों की भीड़ फिर भी साफ-सफाई ऐसी कि बस देखते ही बनती है। सड़क हो, चौराहा हो, अखाड़ा परिसर हो, हर तरफ स्वच्छता ही स्वच्छता दिखाई दे रही है। प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की परिकल्पना को उज्जैन का सिंहस्थ पूरी तरह से साकार कर रहा है। सिंहस्थ मेला के लिए साफ-सफाई के पुख्ता इंतजाम किये गये हैं। विस्तृत कार्य-योजना बनाकर उसका प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है।

उज्जैन सिंहस्थ के लिए व्यापक कार्य-योजना बनाई गई है। इस कार्य-योजना के अनुसार दिन-प्रतिदिन साफ-सफाई की जा रही है। इसके लिये मेला क्षेत्र को चार झोन में बाँटा गया है। पहला झोन महाकाल, दूसरा दत्त अखाड़ा, तीसरा मंगलनाथ तथा चौथा झोन कालभैरव बनाया गया है। इन चार झोन को दो पैकेज महाकाल एवं दत्त अखाड़ा में बाँटा गया है, जिसमें 60 से 70 प्रतिशत मेला क्षेत्र आता है। मंगलनाथ एवं कालभैरव क्षेत्र में भी शेष मेला क्षेत्र कवर हो रहा है। पूरे मेला क्षेत्र में लगभग 10 हजार सफाईकर्मी तैनात किये गये हैं, जो नियमित रूप से साफ-सफाई का काम कर रहे हैं। हर 50 सफाईकर्मी पर एक सुपरवाईजर, हर 5 सुपरवाईजर पर एक सहायक प्रबंधक, 5 सहायक प्रबंधक पर एक प्रबंधक की ड्यूटी लगायी गयी हैं।

साफ-सफाई की व्यवस्था के अलावा कुवेत की इंटरनेशनल वेस्ट मैनेजमेंट कम्पनी तथा मुम्बई की ग्लोबल वेस्ट मैनेजमेंट कम्पनी द्वारा अपने-अपने झोनों में मक्खी एवं मच्छरों के नियंत्रण के लिए सौ-सौ व्यक्तियों के दल लगाये गये हैं। प्रतिदिन दत्त अखाड़ा एवं महाकाल झोन में तीन चलित फॉगिंग मशीनें लगायी गयी है। साथ ही हस्तचलित 12 मशीनें भी कार्यरत है। इसके अलावा 25 स्प्रे मशीन भी लगातार कार्यरत हैं। फॉगिंग एवं कीटनाशक का छिड़काव किया जा रहा है। लार्वा नियंत्रण के लिए जल एकत्रीकरण स्थल पर कीटनाशक का छिड़काव किया जा रहा है। इसके फलस्वरूप मेला क्षेत्र में मक्खी एवं मच्छरों का प्रकोप नहीं दिखाई दे रहा है। सुगंधित लेमन ग्रास ऑईल का छिड़काव नियमित हो रहा है।

क्षिप्रा नदी के पानी की गुणवत्ता को स्नान के लिए बनाये रखने के लिये 5 स्थानों पर ओजोनेशन प्लांट लगाये गये हैं। ये प्लांट गऊघाट, लालपुल, रामघाट, सुनहरी घाट तथा मंगलनाथ में लगाये गये हैं। इसके साथ ही नदी के पानी को बैक्टीरिया रहित बनाने के इंतजाम भी किये गये हैं। नदी के पानी को प्रवाहमान बनाये रखने तथा ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित करने के लिए 100 एरियेटर भी स्थापित किये गये हैं। पानी की गुणवत्ता बनाये रखने के लिए ब्लीचिंग एवं क्लोरिंग पाउडर का उपयोग नहीं किया जा रहा है।

जिला पंचायत अध्यक्ष को मिलेगी निज सहायक की सुविधा

राज्य शासन द्वारा प्रदेश के समस्त जिला पंचायत अध्यक्षों को निज सहायक की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी। जिला पंचायत अध्यक्ष को निज सहायक की सेवाएँ जिला पंचायत के उपलब्ध स्टॉफ में से मिलेगी। इस संबंध में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी आदेश को मध्यप्रदेश पंचायिका में यथावत प्रकाशित किया गया है।

मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक एफ 1-3/2016/22/पं.-1 **भोपाल, दिनांक 31.3.2016**

प्रति,

समस्त कलेक्टर
मध्यप्रदेश

विषय - अध्यक्ष जिला पंचायत को निज सहायक की सुविधा जिला पंचायत के उपलब्ध स्टॉफ से कराने बाबत्।

उपरोक्त विषयक प्रदेश की समस्त जिला पंचायतों को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई घोषणा के अनुक्रम में जिला पंचायत अध्यक्षों को सचिवालयीन सहायता के लिए एक निज सहायक की सेवाएं जिला पंचायत के उपलब्ध स्टॉफ से निम्न शर्तों पर कराई जाये :-

1. ऐसा शासकीय सेवक पदाधिकारी का निकट संबंधी नहीं होना चाहिए।
2. माननीय अध्यक्ष को इस आदेश के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए शासन के विभिन्न विभागों से कर्मचारी की सेवा प्राप्त करने की सुविधा होगी परन्तु ऐसे कर्मचारी के स्थान पर संबंधित विभाग में कोई नियुक्ति नहीं होगी। उक्त निज सहायक अध्यक्ष के साथ अटैच रहेगा और अटैचमेंट के दौरान उसका स्टेटस वहीं बना रहेगा जो अटैचमेंट के पूर्व था और उसे उक्त अवधि में स्थानान्तरित नहीं किया जाएगा।
3. जिला पंचायत अध्यक्ष, उनके जिले के पदस्थ कर्मचारी की ही सेवाएं प्राप्त कर सकेंगे।
4. कोई कर्मचारी जो किसी अन्य कार्यालय में प्रतिनियुक्ति पर है अथवा अटैचमेंट पर है उसे अध्यक्ष के साथ अटैच नहीं किया जा सकता है।
5. अध्यक्ष को उपलब्ध कराये गये निज सहायक के वेतन भत्ते आदि पूर्ववत उसी कार्यालय से आहरित होंगे जहाँ से अटैचमेंट के लिए आहरित होते थे। सभी प्रयोजनों के लिए कर्मचारी का मुख्यालय वही माना जाएगा जहाँ अटैचमेंट के पूर्व था। अध्यक्ष द्वारा जारी उपस्थिति पत्रक के आधार पर संबंधित कार्यालय द्वारा वेतन का भुगतान किया जायेगा। आकस्मिक अवकाश के अलावा अन्य अवकाश, अग्रिम आदि संबंधी कार्यालय प्रमुख द्वारा स्वीकृत होंगे। आकस्मिक तथा ऐच्छिक अवकाश जिला पंचायत के अध्यक्ष स्वीकृत करेंगे तथा उसका रिकार्ड जिला पंचायत कार्यालय संधारित होगा।
6. नियमित कर्मचारियों के मामले में अटैचमेंट की अवधि के दौरान कर्मचारी के गोपनीय चरित्रावली फोल्डर में 'नो रिपोर्ट' प्रमाण पत्र लिखा जायेगा क्योंकि इस अटैचमेंट से कर्मचारी की सेवा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, सेवा-पुस्तिका में अटैचमेंट इंद्राज करने की आवश्यकता नहीं होगी।
7. कर्मचारी की उसकी सहमति के आधार पर ही अध्यक्ष के साथ अटैच किया जाएगा।
8. अध्यक्ष के कार्यकाल समाप्त, पदत्याग, पदमुक्ति आदि पर यह सुविधा स्वमेव समाप्त हो जाएगी।
9. ऐसे कर्मचारी का अटैचमेंट नहीं किया जाएगा जिसके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करने या अभियोजन स्वीकृति का निर्णय सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिया जा चुका है। अचैटमेंट बाद ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाने पर अटैचमेंट समाप्त हो जाएगा तथा माननीय अध्यक्ष को किसी दूसरे निज सहायक की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
10. किसी कारण से निज सहायक की नौकरी समाप्त हो जाने या कंडिका (2) में उल्लेखित संवर्ग के अलावा किसी अन्य संवर्ग में नियुक्ति हो

जाने पर अटैचमेंट स्वतः समाप्त हो जाएगा। ऐसी स्थिति में माननीय अध्यक्ष को किसी दूसरे निज सहायक की सेवाएं प्राप्त करने की सुविधा होगी।

11. माननीय अध्यक्ष अपनी अच्छानुसार निज सहायक का नाम जिला कलेक्टर को सूचित करेंगे। कलेक्टर द्वारा ऐसे निज सहायक की जिले में पदस्थापना की पुष्टि करते हुए कार्यालय प्रमुख के माध्यम से निज सहायक की लिखित सहमति प्राप्त की जाएगी। जिस निज सहायक की सेवाएं चाही गई हों यदि उसकी सेवाएं इस आदेश के अनुसार उपलब्ध कराना संभव नहीं होवे तो कलेक्टर द्वारा माननीय अध्यक्ष को पत्र के माध्यम से वस्तुस्थिति से अवगत कराया जाएगा।

12. अटैचमेंट का आदेश जिला कलेक्टर द्वारा जारी किया जाकर उसकी प्रतिलिपि संबंधित अध्यक्ष, संबंधित कार्यालय प्रमुख तथा निज सहायक को दी जाएगी। संबंधित निज सहायक द्वारा प्रभार सौंपने अथवा ग्रहण करने का प्रतिवेदन नहीं भरा जाएगा। कार्यालय प्रमुख द्वारा कलेक्टर के आदेश के पालन की सूचना अपने नियंत्रणकर्ता अधिकारी, संबंधित अध्यक्ष तथा कलेक्टर को दी जाएगी।

13. निज सहायक के अवकाश अथवा अन्य प्रकार की अनुपस्थिति के दौरान एवजीदार की व्यवस्था नहीं की जाएगी।

(ब्रजेश कुमार)
सचिव
म.प्र. शासन,
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

प्रदेश को मनरेगा के लिये 1053 करोड़ रुपये

प्रदेश को मनरेगा में 1053 करोड़ रुपये की राशि भारत सरकार से प्राप्त हुई है। इस राशि से मनरेगा के क्रियान्वयन में तेजी आयेगी। प्राप्त राशि से प्राथमिकता से मजदूरी का भुगतान करवाने के निर्देश दिए गए हैं।

वर्तमान में प्रदेश में तकरीबन चार लाख से अधिक कार्य प्रगतिरत हैं। प्राप्त राशि से इन कार्यों को शीघ्रता से पूरा करवाया जायेगा। मजदूरों की बकाया राशि का भी भुगतान किया जायेगा। उल्लेखनीय है कि मनरेगा में काम करने वाले अकुशल श्रमिकों की एक दिन की मजदूरी एक अप्रैल 2016 से 167 रुपये की गयी है।

इकत्तीस मई को अंतर्राष्ट्रीय तम्बाकू एवं धूम्रपान निषेध दिवस का आयोजन

मध्यप्रदेश शासन के सामाजिक न्याय विभाग द्वारा प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी 31 मई को अन्तर्राष्ट्रीय तम्बाकू एवं धूम्रपान निषेध दिवस का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन का उद्देश्य लोगों में बढ़ती तम्बाकू और धूम्रपान के सेवन की प्रवृत्ति को रोकने एवं उन्हें इनके दुष्परिणामों से अवगत कराना है। इस संबंध में राज्य शासन द्वारा जारी आदेश को मध्यप्रदेश पंचायिका में यथावत प्रकाशित किया गया है।

सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण संचालनालय, मध्यप्रदेश
1250 तुलसी नगर भोपाल-462003
दूरभाष नं.-0755-2556916, फैक्स नं. 0755-2552665

क्रमांक/एफ-1-30/नशाबंदी/2016-17/156 **भोपाल, दिनांक 5.5.2016**
5.5.2016

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश
2. समस्त पुलिस अधीक्षक, मध्यप्रदेश
3. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत मध्यप्रदेश
4. संयुक्त संचालक/उप संचालक
सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण, मध्यप्रदेश

विषय - 31 मई 2015 को 'अन्तर्राष्ट्रीय तम्बाकू एवं धूम्रपान निषेध दिवस' के आयोजन बावत्।

प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी 31 मई 2016 को 'अन्तर्राष्ट्रीय तम्बाकू एवं धूम्रपान निषेध दिवस' का आयोजन किया जाना है। इसका उद्देश्य युवाओं, छात्र, छात्राओं एवं जनसामान्य में बढ़ती हुई तम्बाकू/धूम्रपान के सेवन की प्रवृत्ति की रोकथाम के लिए तम्बाकू एवं बीड़ी, सिगरेट के दुष्परिणामों से अवगत कराना है, ताकि तम्बाकू एवं गुटखा, बीड़ी, सिगरेट के सेवन की बढ़ती प्रवृत्ति से युवाओं एवं जनसामान्य को कैंसर, टी.बी., हृदयाघात की बीमारियों से बचाया जा सके तथा तम्बाकू एवं धूम्रपान के सेवन की रोकथाम हेतु जनजागृति का वातावरण निर्माण हो सके।

अन्तर्राष्ट्रीय तम्बाकू एवं धूम्रपान निषेध दिवस का सफल आयोजन के लिये अनुरोध है कि म.प्र. शासन, गृह विभाग के पत्र क्र./डी 4218/आर 4351/2011/दो/सी-1 दिनांक 20 सितम्बर 2011 से प्रतिबंधित मादक द्रव्यों की रोकथाम के लिये जिला स्तर पर गठित जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति की बैठक आयोजित कराई जाकर नशामुक्ति के लिये जनजागृति के वृहद कार्यक्रमों का आयोजन कराया जावे।

इस अवसर पर तम्बाकू एवं धूम्रपान के सेवन के दुष्परिणामों पर आधारित कार्यक्रम जैसे - सेमीनार, रैली, पोस्टर प्रदर्शनी, वाद-विवाद, निबंध-लेखन, प्रश्नमंच, चित्रकला प्रतियोगिताएँ व नुक्कड़ नाटक, गीत, नृत्य आदि आयोजित किये जावें। इन कार्यक्रमों में विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय, नगर पालिका, नगर निगम, जिला पंचायत, जनपद पंचायत, स्वैच्छिक संस्थाएँ तथा स्थानीय जनप्रतिनिधि सम्मिलित हों। यह हमारा दायित्व है कि तम्बाकू, सिगरेट, धूम्रपान की बढ़ती नशा प्रवृत्ति से बचाव के लिए प्रदेश के हर युवा, वृद्ध, नागरिकों को पहल करना होगी।

अतः इस दिवस पर उपरोक्तानुसार कार्यक्रम आवश्यक रूप से आयोजित करते हुए, आयोजित कार्यक्रम का प्रतिवेदन संलग्न निर्धारित प्रपत्र में भिजवाने का कष्ट करें।

(अजीत कुमार)
संचालक
सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन
कल्याण, मध्यप्रदेश

ग्राम पंचायत सचिवों के रिक्त पदों की पूर्ति

पंचायत राज संचालनालय, मध्यप्रदेश
1, अरेरा हिल्स, तिलहन संघ परिसर, भोपाल
(Telephon No. 0755-2557727, Fax No. 0755-2552899)
(E-mail address; dirpanchayat@mp.gov.in)

क्रमांक/पं.रा./पंचा.-626/2016/5495 **भोपाल, दिनांक 11.05.2016**

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत समस्त, मध्यप्रदेश

विषय - ग्राम पंचायत सचिवों के रिक्त पदों की पूर्ति करने के संबंध में।

संदर्भ - 1. मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का परिपत्र क्रमांक एफ-1-9/2012/22/पं.-1, दिनांक 03 अक्टूबर 2012
2. संचालनालय का पत्र क्रमांक/पंचा/626/2013/7657, दिनांक 25.7.2013
3. संचालनालय का पत्र क्रमांक/पं.रा./पंचा-626/2015/18545, दिनांक 31.12.2015

विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें। मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ-1-9/2012/22/पं.-1, दिनांक 03 अक्टूबर 2012 द्वारा ग्राम पंचायत सचिवों के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु मापदण्ड निर्धारित कर निर्देश जारी किये गये हैं।

कई जिलों में ग्राम पंचायत सचिवों के पद रिक्त होने से शासकीय कार्य संचालन में कठिनाई आ रही है। कहीं-कहीं ग्राम पंचायत सचिवों को दो-दो ग्राम पंचायत सचिवों का कार्य सौंपा गया है। ग्राम पंचायत सचिवों की रिक्त पदों की पूर्ति मध्यप्रदेश पंचायत सचिव सेवा भर्ती नियम 2011 के तहत विज्ञापन जारी कर की जानी है। रिक्त पदों की पूर्ति मार्च 2016 तक की जानी थी।

अतः शासन के निर्देशों के अनुसार आपके जिले के अंतर्गत ग्राम पंचायत सचिवों के रिक्त पदों की पूर्ति मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत सचिव सेवा भर्ती नियम 2011 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही कर पदों की पूर्ति तत्काल की जाकर संचालनालय को संलग्न प्रपत्र में जानकारी भेजना सुनिश्चित करें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

(संतोष मिश्र)
संचालक सह आयुक्त
पंचायत राज संचालनालय
मध्यप्रदेश

//प्रपत्र//

ग्राम पंचायत सचिवों के रिक्त/भरे पदों की जानकारी

जिले का नाम ....

क्र.	जनपद पंचायत का नाम	स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद	दिसम्बर 15 से मार्च 2016 के मध्य रिक्त पदों की पूर्ति के संबंध में की गई कार्यवाही का विवरण
1	2	3	4	5	6

हस्ता/-